वर्ष 12 • अंक 270 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 31 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

रतन इंडिया का बिजली संयंत्र आखिर बिका

विनोद कुमार यादव पृष्ठ 4

निगमीकरण चाहता है रेलवे, निजीकरण नहीं

डॉलर रु. 71.30 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 79.90 ▲ 40 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38822 ▲ 34 रुपये | सेंसेक्स 41558.80 ▼ 17.10 | निफ्टी 12255.80 ▲ 10.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12329.30 ▲ 73.50 | ब्रेंट क्रूड 67.90 डॉलर ▲ 0.40 डॉलर

एक नज़र

एसबीआई ने बाहरी मानक आधारित उधारी दर घटाई

देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सोमवार को अपनी बाहरी मानक आधारित दर (ईबीआर) में 25 आधार अंक की कमी की। इस कटौती के बाद बैंक का ईबीआर 8.05 प्रतिशत से कम होकर 7.80 प्रतिशत रह गया है। नई दर 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी। बैंक ने कहा कि दर में कमी से ईबीआर से जुड़े आवास ऋण ग्राहक साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दर 25 आधार अंक तक कम हो जाएगी।

खरीदार नहीं मिला तो बंद होगी एयर इंडिया: अधिकारी

वित्तीय संकट में फंसी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को अगर खरीदार नहीं मिला तो अगले साल जून तक उसे परिचालन बंद करने के लिए मजूबर होना पड़ सकता है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि टुकड़ों-टुकड़ों में पूंजी की व्यवस्था से लंबे समय तक गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है। 12 छोटे विमान खड़े हैं जिन्हें फिर से चलाने के लिए पूंजी की जरूरत है। कंपनी पर करीब 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज है और सरकार उसके विनिवेश के तौर-तरीकों पर काम कर रही है।

आज का सवाल

क्या 5जी परीक्षण में हुआवे को भाग लेने की अनुमति देना है सही निर्णय

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अगले वित्त वर्ष देश की आर्थिक विकास दर में आएगी तेजी — हां **25.00%**, नहीं **75.00%**

सहकारी बैंकों पर होगी सख्ती

भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए जारी किया परिपत्र का मसौदा

अनूप रॉय
मुंबई, 30 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ऋण देने की शर्तें सख्त बनाने जा रहा है। इसके तहत ये बैंक अपने कुल ऋण का आधा हिस्सा ही व्यक्तियों और समूहों को दे सकेंगे। इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से कम से कम आधा ऋण 25 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्यों को बढ़ाना होगा।

आरबीआई ने आज इससे संबंधित परिपत्र का मसौदा जारी किया। इसके मुताबिक यूसीबी को ये सभी बदलाव 31 मार्च, 2023 तक अपनाने होंगे। पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कॉओपरेटिव बैंक (पीएमसी) में हाल में सामने आए घोटाले के बाद केंद्रीय बैंक ने यूसीबी के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। पीएमसी में खुलासा हुआ है कि उसके प्रबंधन ने फर्जीवाड़ा करके एक ही समूह को 70 फीसदी से अधिक ऋण दिया था।

इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए नए नियम बनाने का फैसला किया था। ये बैंक राज्य सरकारों और बैंकिंग नियामक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आरबीआई का कहना है कि नए नियमों से यूसीबी किसी व्यक्ति या समूह को ज्यादा ऋण देने के जोखिम से बचेंगे और वित्तीय समावेश के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।

यूसीबी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य उनकी कुल उधारी का 75 फीसदी करने का प्रस्ताव है जो अभी 40 फीसदी है। मार्च 2021 तक इसे 50 फीसदी, मार्च 2022 तक 60 फीसदी और मार्च 2023 तक 75 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य है।

केंद्रीय बैंक का कहना है कि यूसीबी की एकल और समूह उधारी की सीमा बैंक की टियर-1 पूंजी की क्रमश: 10 फीसदी और 25 फीसदी होनी चाहिए। अब तक वे अपने पूंजी फंड का 15 फीसदी एकल उधारकर्ता को और 40 फीसदी समूह उधारकर्ता को दे सकते थे। ऋण देने की संशोधित क्षमता यूसीबी द्वारा दिए जाने वाले सभी ऋणों पर लागू होगी। उनके द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से कम से कम आधा ऋण 25 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों तरह के ऋण शामिल हैं। मौजूदा यूसीबी को 31 मार्च, 2023 तक अपने ऋण का हिसाब किताब नए नियमों के मुताबिक ढालना होगा। इस प्रयोजन के लिए ऋण में सभी तरह के वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित ऋण शामिल होंगे।

आरबीआई के परिपत्र के मसौदे में कहा गया है कि अगर सावधि ऋण या गैर वित्त पोषित है तो यह भुगतान की अवधि या परिपक्वता तक जारी रह सकता है। टियर-1 पूंजी बैंक की प्रमुख पूंजी होती है जबकि पूंजी फंड में चुकता पूंजी और मुक्त भंडार शामिल होता है। ऋण में वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित उधारी सीमा और अंडरराइटिंग तथा इस तरह की अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल होती हैं। आरबीआई ने परिपत्र के मसौदे में कहा है कि बैंकों के एकल या आपस में संबंध रखने वाले उधारकर्ताओं के समूह को ज्यादा ऋण देने से जोखिम बढ़ता है। जब ऐसे किसी उधारकर्ता को दिया गया ऋण फंस जाता है तो इससे संबंधित बैंक की पूंजी/हैसियत बुरी तरह प्रभावित होती है और कभी-कभार नकदी संकट और दिवालिया होने की नौबत भी आ जाती है।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों को संशोधित नियमों और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्यों के पालन के लिए अपने निदेशक मंडल से एक कार्ययोजना की मंजूरी लेनी होगी। परिपत्र के मसौदे पर 20 जनवरी, 2020 तक सुझाव दिया जा सकता है।

मसौदे की खास बातें

- प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देना होगा **75** फीसदी ऋण, अभी यह सीमा **40** फीसदी
- कुल ऋण में से आधे ऋण का आकार **25** लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए
- एकल और समूह उधाकर्ताओं के लिए ऋण सीमा क्रमश: **10** और **25** फीसदी करने का प्रस्ताव

हुआवे भी भाग लेगी 5जी सेवा परीक्षण में

मेघा मनचंदा एवं एजेंसियां
नई दिल्ली, 30 दिसंबर

अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों में कथित जासूसी के आरोपों में घिरी चीन की दिग्गज दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी हुआवे के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने देश में 5जी के परीक्षण में हुआवे सहित सभी उपकरण विनिर्माताओं को भाग लेने की इजाजत दे दी है। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को इस बारे में कहा, 'हमने सभी दूरसंचार कंपनियों को 5जी स्पेक्ट्रम के परीक्षण में भाग लेने की इजाजत देने का निर्णय लिया है।' प्रसाद ने कहा कि आने वाले समय में 5जी तकनीक का ही बोलबाला रहेगा, इसलिए भारत 5जी में नवाचार को बढ़ावा देगा।

सरकार का यह निर्णय हुआवे के लिए बड़ी राहत है। भारत सहित दुनिया भर में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की वजह से चीन की इस कंपनी को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। चालू कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में हुआवे भारत में 5जी खंड में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दी।

सरकार के इस निर्णय के बाद हुआवे इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी जे चेन ने कहा, 'हमने मीडिया में यह खबर देखी है। हुआवे में भरोसा दिखाने के लिए हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं। हमारा मानना है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को ऊपर उठाने में नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाला नेटवर्क अहम भूमिका निभाएंगे। हुआवे भारत और यहां के दूरसंचार उद्योग को लेकर प्रतिबद्ध है।'

इससे पहले चेन ने कहा था कि कंपनी भविष्य में 5जी का सबसे बड़ा बाजार बनने वाले भारत में संभावनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहती है। ■ शेष पृष्ठ 2

- सरकार का निर्णय हुआवे के लिए है बड़ी राहत
- सुरक्षा संबंधी मुद्दों की वजह से हुआवे को देखा जाता है संदेह की दृष्टि से

अरबपतियों की सूची से कुछ बड़े बाहर

इस सूची से अनिल अंबानी और सुभाष चंद्रा जैसे दिग्गज हो गए बाहर

कृष्ण कांत
मुंबई, 30 दिसंबर

भारत के अरबपति समूह में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2019 में इस सूची में 10 प्रवर्तक शामिल हुए हैं। कॉर्पोरेट आय कर में कमी की घोषणा के बाद इन प्रवर्तकों की कंपनियों के शेयरों में बड़ी बढ़त दर्ज की गई, जिनके दम पर इन्होंने अपना नाम इस फेहरिस्त में जोड़ लिया। दूसरी तरफ 12 प्रवर्तक इस फेहरिस्त से बाहर हो गए हैं। इनकी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में कमी या उनके द्वारा हिस्सेदारी बेचने की कवायद इसकी वजह हो सकती है। जिन लोगों ने इस फेहरिस्त में अपने नाम जोड़े हैं उनमें रिलेक्सो फुटवीयर्स के रमेश दुआ, पीआई इंडस्ट्रीज के मयंक सिंघल और प्रेस्टीज एस्टेट्स के इरफान रज्जाक सबसे आगे रहे हैं। अनिल अंबानी, येस बैंक के राणा कपूर और ऐस्सल ग्रुप के सुभाष चंद्रा कुछ बड़े नाम हैं, जो इस वर्ष इस फेहरिस्त से बाहर हो गए।

इस बड़े बदलाव का नतीजा यह रहा है कि दिसंबर 2019 में इस समूह का आकार कम होकर 78 रह गया है, जो दिसंबर 2018 में 80 हुआ करता था। यह विश्लेषण 28 दिसंबर 2019 तक प्रवर्तकों की 1 अरब डॉलर या इससे अधिक शुद्ध परिसंपत्तियों पर आधारित है। इनकी शुद्ध परिसंपत्तियों का आकलन डॉलर-रुपये का मासिक विनिमय दर 71 मानते हुए किया गया है। 2019 में उपभोक्ता वस्तु विनिर्माता, रियल एस्टेट डेवलपर और खुदरा बैंक सर्वाधिक फायदे में रहे हैं, जबकि दवा उद्यमी, वाहन निर्माता और पूंजीगत वस्तु कंपनियों के मालिकों की संपत्ति में वर्ष में तेज गिरावट देखी गई है।

विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों ने उपभोक्ता-मांग से जुड़े शेयरों को अधिक तवज्जो दी है, जिस वजह से यह स्थिति बनी है। इक्विनॉमिक्स ऐंड एडवाइजरी सर्विसेस के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक जी चोकालिंगम कहते हैं, 'मौजूदा समय मुनाफे में चलने वाली उपभोक्ता वस्तु कंपनी या खुदरा कर्जदाता के प्रवर्तकों के लिए शानदार रहा है। अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में सुस्ती के बाद भी इन खंडों का प्रदर्शन जानदार रहा है।' ■ शेष पृष्ठ 12

प्रवर्तक जिन्हें मिली बढ़त

प्रवर्तक हिस्सेदारी : ■ 2018 ■ 2019
▲ % बदलाव (करोड़ रुपये में)

रमेश कुमार दुआ
रिलेक्सो फुटवियर्स
6,561.8
10,804.8
64.7%

मयंक सिंघल
पीआई इंडस्ट्रीज
6,078.9
10,357.4
70.4%

इरफान रज्जाक
प्रेस्टिज इंडस्ट्रीज
5,757.9
8,830.5
53.4%

जी मल्लिकार्जुन राव
जीएमआर इन्फ्रा
6,247.2
8,100.0
29.7%

संजय अग्रवाल
एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक
5,843.9
7,822.7
33.9%

खबरों में रहे स्टॉक

टाटा मोटर्स

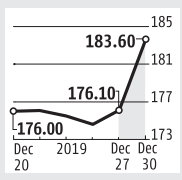

एसऐंडपी बीएसई-100 इंडेक्स में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर

₹ 176.10 पिछला बंद भाव
₹ 183.60 आज का बंद भाव
▲ 4.26 %

गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स

स्नोमैन की 40.25 फीसदी हिस्सेदारी अदाणी लॉजिस्टिक्स को बेचेगी

₹ 109.75 पिछला बंद भाव
₹ 122.40 आज का बंद भाव
▲ 11.53 %

आईनॉक्स लीजर

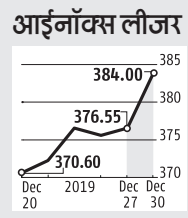

इंदौर में चार अतिरिक्त स्क्रीन का वाणिज्यिक परिचालन

₹ 376.55 पिछला बंद भाव
₹ 384.00 आज का बंद भाव
▲ 1.98 %

मणप्पुरम फाइनैंस

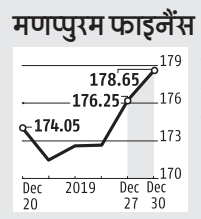

एनसीडी के जरिये 350 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

₹ 176.25 पिछला बंद भाव
₹ 178.65 आज का बंद भाव
▲ 1.36 %

आईजी पेट्रोकेमिकल्स

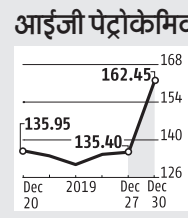

केमिकल शेयरों में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला

₹ 135.40 पिछला बंद भाव
₹ 162.45 आज का बंद भाव
▲ 20.00 %

संक्षेप में

केजी-डी6 से बाहर निकली कनाडा की निको

रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की बीपी-पीएलसी से 3.6 करोड़ डॉलर का भुगतान प्राप्त कर कनाडा की निको रिसोर्सेज पूर्वी अपतटीय केजी-डी6 ब्लॉक की हिस्सेदारी से बाहर निकल गई है। निको परियोजना में अपने हिस्से की देनदारी पूरी नहीं कर रही थी। निको ने बयान में कहा कि वह केजी-डीडब्ल्यूएन-98-3 ब्लॉक से बाहर निकल गई है और उसकी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रिलायंस तथा बीपी ने खरीदी है। निको को 3.6 करोड़ डॉलर का भुगतान किया गया है। निको लिमिटेड के पास इस ब्लॉक की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी शेष भागीदारों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके बाद केजी-डी6 ब्लॉक में रिलायंस की हिस्सेदारी 60 से बढ़कर 66.67 प्रतिशत हो गई है। वहीं बीपी की हिस्सेदारी 30 से बढ़कर 33.33 प्रतिशत हो गई है। *भाषा*

इंडियन बैंक 3 जनवरी से करेगा ब्याज दर में बदलाव

इंडियन बैंक ने सोमवार को विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले ऋण पर कोष की सीमांत लागत आधारित दर (एमसीएलआर) में बदलाव की घोषणा की। नई दरें तीन जनवरी से लागू होंगी। बैंक ने बंबई शेयर बाजार को बताया, 'एक दिन की परिपक्वता अवधि वाले कर्ज के एमसीएलआर को 7.95 प्रतिशत से संशोधित करके 7.90 प्रतिशत किया गया है। हालांकि, एक महीने के कर्ज का एमसीएलआर मौजूदा समय में आठ प्रतिशत से बढ़कर 8.05 प्रतिशत कर दिया गया है। *भाषा*

अक्टूबर में जियो से जुड़े 91 लाख ग्राहक

रोमिता मजूमदार
मुंबई, 30 दिसंबर

इस साल का त्योहारी सीजन मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस जियो के लिए अच्छा रहा और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर माह में कंपनी के ग्राहकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है। जियो ने बताया कि अक्टूबर माह में कंपनी के ग्राहकों में 91 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं और यह तीसरी बार है जब किसी एक माह में 90 लाख से अधिक नए ग्राहक कंपनी से जुड़े।

इससे पहले जनवरी 2019 में जियो ने 93 लाख तथा फरवरी 2019 में 94 लाख नए ग्राहक जोड़े थे। प्रतिस्पर्धी दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल के ग्राहकों में मामूली बढ़ोतरी हुई है और दोनों कंपनियों ने क्रमश: 1,89,901 तथा 81,974 नए ग्राहकों को जोड़ा। वायरलैस सबस्क्रिप्शन के मामले में वोडाफोन-आइडिया की कुल बाजार हिस्सेदारी 31.49 प्रतिशत है। इसमें जियो की 30.79 प्रतिशत तथा एयरटेल की 27.52 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल ने बताया था कि सितंबर महीने में उनके कुल ग्राहकों की संख्या में 49 लाख की कमी आई थी। वहीं, जियो भी सितंबर महीने में नए ग्राहकों की औसत संख्या को बरकरार नहीं रख सका तथा 70 लाख से भी कम नए ग्राहकों को ही जोड़ सका। अक्टूबर महीने के आखिर में जियो ने दूसरे नेटवर्क पर फोन कॉल करने पर इंटरकनेक्शन शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालांकि इस कदम का पूरा असर नवंबर के आंकड़ों में दिखाई देगा।

भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या सितंबर के 119.52 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर में 120.48 करोड़ हो गई है और इस लिहाज से मासिक वृद्धि दर 0.80 प्रतिशत रही। अक्टूबर माह में शहरी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 68.16 करोड़ हो गई जो सितंबर माह में 67.79 करोड़ थी। इसी तरह, ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या अक्टूबर माह में 52.31 करोड़ हो गई जो सितंबर माह में 51.72 करोड़ थी। इस तरह, अक्टूबर महीने में मासिक आधार पर ग्राहक सबस्क्रिप्शन वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र में 1.14 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 0.55 प्रतिशत रही।

जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में इस महीने वायरलैस सबस्क्रिप्शन वृद्धि दर नकारात्मक 0.39 प्रतिशत रही। इस अवधि में सर्वाधिक वायरलैस सबस्क्रिप्शन वृद्धि दर मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र में (2.86 प्रतिशत) रही।

अक्टूबर माह में वायरलाइन सबस्क्रिप्शन 0.20 प्रतिशत गिरावट के साथ 214.9 लाख से घटकर 214.5 लाख रह गया। वायरलाइन सबस्क्रिप्शन आंकड़ों में शहरी और ग्रामीण हिस्सेदारी क्रमश: 87.49 प्रतिशत और 12.51 प्रतिशत रही है। शीर्ष पांच वायरलाइन ब्रांडबैंड सेवा प्रदाताओं में बीएसएनएल (86.2 लाख), भारती एयरटेल (24 लाख), अटरिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज (14.9 लाख), हैथवे केबल ऐंड डेटाकॉम (8.7 लाख) और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (7.9 लाख) शामिल हैं। शीर्ष पांच वायरलैस ब्रांडबैंड सेवा प्रदाताओं में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (3642.3 लाख), भारती एयरटेल (1304.5 लाख), वोडाफोन आइडिया (1157.8 लाख), बीएसएनएल (136.4 लाख) और एमटीएनएल (दो लाख) शामिल हैं।

किन कंपनियों से कितने नए ग्राहक जुड़े

- तीसरी बार जियो ने एक माह में जोड़े 90 लाख ग्राहक
- वोडाफोन-आइडिया के ग्राहकों में 1,89,901 की बढ़ोतरी
- अक्टूबर माह में एयरटेल ने जोड़े 81,974 ग्राहक
- फिलहाल वायरलैस सबस्क्रिप्शन बाजार में वोडाफोन-आइडिया की कुल हिस्सेदारी 31.49 प्रतिशत
- भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या सितंबर के मुकाबले 0.80 प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर में 120.48 करोड़ पर पहुंची

चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करेगा वेब पोर्टल

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में रहने वालों लोगों को अपने मोबाइल फोन खोने पर थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जो चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने तथा ट्रैक करने में सक्षम होगा। यह पहल इस साल सितंबर में मुंबई में शुरू की गई थी और अब इसे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए भी शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2020 में इसे देश के अन्य हिस्सों में विस्तारित किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए शुरू किए गए सीईआईआरडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही, संबंधित मोबाइल फोन को सभी मोवाइल नेटवर्क के लिए ब्लॉक करने, मोबाइल को ट्रैक करने तथा संबंधित डेटा पुलिस के साथ साझा करने के विकल्प मौजूद हैं। मोबाइल मिलने पर उसे अनब्लॉक किया जा सकता है।

5जी परीक्षण में हुआवेई...

पृष्ठ 1 का शेष

चेन ने यह भी कहा था कि भारत अपने आप में एक अनोखा बाजार है और इसे गहराई से समझने के साथ आपको दीर्घ अवधि की नीति अपनानी होगी।

5जी परीक्षण में हुआवे की शिरकत पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार ने अपने मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। परीक्षण के बाद ही देश में पूर्ण रूप से 5जी सेवाओं की शुरुआत होगी।हुआवे पर ऐसे आरोप लगे हैं कि उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार उपकरणों की मदद से अमेरिकी कंपनियों एवं एजेंसियों की जासूसी की है। चीन की यह कंपनी ऑस्ट्रेलिया और जापान में प्रतिबंधित है, जबकि रूस, तुर्की और सउदी अरब ने कंपनी का स्वागत किया है।

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल हुआवे के समर्थन में पहले ही आगे आ चुके हैं। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में मित्तल ने कहा कि पिछले एक दशक में कंपनी ने अपने उत्पादों के साथ एक अच्छी मिसाल पेश की है। मित्तला ने कहा था, 'जहां तक अपने 4जी और 4जी सेवाओं में कंपनी के उत्पादों का अनुभव किया है उस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह एरिक्सन और नोकिया से काफी बेहतर है।'

हुआवे 5जी खंड में शीर्ष ओहदा हासिल करने के लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा कर रही है। कंपनी ने अब तक 50 व्यावसायिक 5जी अनुबंध हासिल किए हैं। इनमें 28 यूरोप, 11 मध्य एशिया, 6 एशिया-प्रशांत, 4 दक्षिणी अमेरिका और 2 अफ्रीका में शामिल हैं।

अगले महीने शुरू होगा मोनेट का स्टील संयंत्र

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 30 दिसंबर

एयॉन और जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से अधिग्रहीत मोनेट इस्पात स्टील की मांग में बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में अगले महीने एकीकृत स्टील परिचालन शुरू करने पर विचार कर रही है। जेएसडब्ल्यू के संयुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी (समूह) शेषगिरि राव ने कहा, हमने पैलेट प्लांट की क्षमता 24 लाख टन करने का काम पूरा कर लिया है और हम अगले महीने से एकीकृत स्टील परिचालन भी शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में मोनेट के लिए स्थितियां बेहतर नजर आएंगी।

अभी एकीकृत परिचालन पूरी तरह बंद है। मोनेट पर बैंकों का 11,000 करोड़ रुपये बकाया था और यह कंपनी दिवालिया संहिता के तहत आरबीआई की तरफ से बनाई गई 12 एनपीए खाते की सूची में शामिल थी। एयॉन और जेएसडब्ल्यू स्टील (अल्पांश साझेदार) की 2,875 करोड़ रुपये की समाधान योजना को एनसीएलटी ने जुलाई 2018 के आखिर में मंजूरी दी थी। जेएसडब्ल्यू की दूसरी तिमाही के नतीजे में कहा गया था कि स्टील परिचालन पर पहले घोषित रखरखाव के लिए बंदी और मरम्मत का असर पड़ा था।

अक्टूबर में मोनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि वह स्टील के विशेष उत्पादों के लिए प्लांट व मशीनरी में सुधार करेगी। पैलेट प्लांट व डीआरआई के अलावा प्लांट को बंद करने की अवधि 21 जून से प्रभावी हुई और इसे आगे भी विस्तार दिया गया। अब प्लांट में सुधार के बाद एकीकृत परिचालन फिर से शुरू होगा क्योंकि सुधार का काम 2019-20 की चौथी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।

अधिग्रहण व प्रबंधन पर नियंत्रण के बाद रायगढ़ पैलेट प्लांट का परिचालन अक्टूबर में शुरू हुआ था और उत्पादन क्षमता के करीब 90 फीसदी तक उत्पादन हुआ। इसके बाद फरवरी में मोनेट ने एकीकृत स्टील उत्पादन ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आदि के जरिए शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व दिसंबर 2018 के 493.82 करोड़ रुपये के मुकाबले सितंबर 2019 में 660.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। जून 2019 में राजस्व 777.09 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था।

हालांकि पिछले साल के आखिर में स्टील बाजार में कमजोरी के संकेत आने शुरू हो गए थे। स्टील की कीमतें नवंबर 2018 में 46.000 रुपये प्रति टन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था, लेकिन तब से इसमें गिरावट शुरू हुई और यह हाल में करीब 32,500 रुपये प्रति टन था। तैयार स्टील की खपत की रफ्तार काफी तेजी से घटी है और यह वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही के 10.3 फीसदी के मुकाबले वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 3.1 फीसदी रह गई।

हालांकि पिछले दो महीने में कीमतें बढ़ी हैं। इसकी वजह बुनियादी ढांचा व निर्माण क्षेत्र के अलावा खुदरा मांग रही। अक्टूबर व नवंबर में कंपनियों ने कीमतों में करीब 1,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की। मोनेट की उत्पादन क्षाता 12-13 लाख टन है। हालांकि वहां उत्पादन क्षमता 30 लाख टन तक करने के लिए जमीन उपलब्ध है। मोनेट अगले साल कायापलट की उम्मीद कर रही है।

आईएलऐंडएफएस फाइ. को घाटा

सुब्रत पांडा
मुंबई, 30 दिसंबर

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज की वित्तीय सेवा इकाई आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज (आईफिन) का शुद्ध नुकसान वित्त वर्ष 2019 में 13,272 करोड़ रुपये रहा जबकि इससे एक साल पहले कंपनी ने 9.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

कंपनी का शुद्ध राजस्व भी वित्त वर्ष 2019 में 87.22 फीसदी घटकर 288.88 करोड़ रुपये रह गया, जो वित्त वर्ष 2018 में 2,261.93 करोड़ रुपये रहा था। इसके अलावा कंपनी ने जो कर्ज दिया था उनमें 12,429 करोड़ रुपये गैर-निष्पादित आस्तियां हो गईं और इसके लिए कंपनी ने 11,697 करोड़ ररुपये का प्रावधान किया है।

मार्च 2019 में आईफिन की लोनबुक 12,945 करोड़ रुपये की थी, जिसमें से 96 फीसदी कर्ज गैर-निष्पादित आस्तियां हैं। अंडर-परफॉर्मिंग लोन 35.12 करोड़ रुपये का रहा जबकि मानक कर्ज 480.44 करोड़ रुपये का। मार्च 2019 के आखिर में कंपनी की देनदारी 16,635.72 करोड़ रुपये रही। आईफिन को आईएलऐंडएफएस के निदेशक मंडल ने रेड कंपनी के तौर पर वर्गीकृत किया है, जहां वह अपनी कर्ज देनदारी को पूरा करने में सक्षम नहीं है, न तो सुरक्षित कर्ज बल्कि असुरक्षित कर्ज के लिए भी। कंपनी की कुल उधारी मार्च 2019 के आखिर में विभिन्न जरिये मसलन कर्ज वाली प्रतिभूतियां, बैंक कर्ज, वाणिज्यिक प्रतिभूतियों और अंतर-कंपनी जमाओं से 14,916 करोड़ रुपये थी।

रतन इंडिया का ऋणग्रस्त संयंत्र आखिर बिका

ऋणदाताओं को मिलेंगे 4,050 करोड़ रुपये, खरीदारों में विदेशी निवेशक भी शामिल

श्रेया जय
नई दिल्ली, 30 दिसंबर

रतनइंडिया की 1,350 मेगावॉट क्षमता की अमरावती विद्युत परियोजना का ऋण पुनर्गठन नए ऋणदाताओं की मदद से पूरा हो गया है। गोल्डमैन सैक्स और वर्डे पार्टनर्स मौजूदा ऋणदाताओं के कुल कर्ज का 4,050 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी। इसमें परियोजना में 15 प्रतिशत की इक्विटी भी शामिल है। नए ऋणदाताओं ने इस सौदे के लिए आदित्य बिड़ला ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) का इस्तेमाल किया है।

ऋणदाताओं के कंसोर्टियम का कुल कर्ज 6,296 करोड़ रुपये था। इसमें पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा 36 प्रतिशत की कर्जमाफी शामिल होगी। इन परियोजनाओं से 12 ऋणदाता जुड़े हुए थे जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, ऐक्सिस बैंक मुख्य रूप से शामिल हैं।

रतन इंडिया समूह के चेयरमैन राजीव रतन ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय परिसंपत्तियों को लेकर विदेशी ऋणदाताओं की दिलचस्पी देखी गई थी। उन्होंने कहा, 'यह अपने तरह का पहला सौदा है जिसमें ताजा पूंजी लगाई जा रही है। नए ऋणदाताओं के समूह में विदेशी ऋणदाता भी शामिल हैं जो इस क्षेत्र के लिए नया है।'

अमरावती विद्युत क्षेत्र में 40 फंसी हुई परिसंपत्तियों की सूची में शामिल है। इस परियोजना के संदर्भ में दो कर्ज-पुनर्गठन हो चुके हैं, जिनमें फरवरी 2018 में आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के संबंध में दूसरा पुनर्गठन पूरा नहीं हो सका। इस सर्कुलर में बैंकों को सभी फंसी परिसंपत्तियां 180 दिन में सुलझाने या एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया शुरू किए जाने का निर्देश दिया गया था। सितंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश में इस सर्कुलर को अमान्य करार दिया गया था।

आरबीआई के नए 'प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड ऐसेट्स' के तहत अमरावती के ऋणदाताओं ने परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि परियोजना से बेची जाने वाली बिजली की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) में दर में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है।

अमरावती की विद्युत दर का स्तर 3.26 रुपये प्रति यूनिट है और परियोजना लागत 7,493 करोड़ रुपये थी। परियोजना को कोल इंडिया से कोयला आपूर्ति की किल्लत की वजह से विलंब का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से राज्यों से भुगतान में देरी होने से लागत बढ़ गई।

कंपनी की आगामी योजनाओं के बारे में रतन ने कहा कि ताप विद्युत क्षेत्र में वह फिलहाल कोई नया निवेश नहीं करेंगे। उन्होंने बताया, 'ताप विद्युत क्षेत्र में नए निवेश की हमारी कोई योजना नहीं है। हालांकि अमरावती में हमारे पास जमीन, कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति है, इसलिए परियोजना का विस्तार कर सकते हैं और इसके दूसरे चरण का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि मौजूदा संयंत्र के कानूनी मामले को कब तक सुलझा लिया जाएगा।'

रतन का मानना है कि परियोजना को संकट में डालने वाली समस्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र में लगातार सुधार आ रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट प्रणाली से भुगतान व्यवस्था में सुधार आया है।' मौजूदा कोयला आपूर्ति को देखते हुए कंपनी ने परियोजना को 60 प्रतिशत के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर संचालित करने की योजना बनाई है। यह अभी 40 प्रतिशत है। अमरावती परियोजना ने 55 लाख टन आपूर्ति के लिए कोल इंडिया की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता किया है।

विद्युत क्षेत्र का पहला ऋणग्रस्त संयंत्र

- रतनइंडिया की अमरावती परियोजना में गोल्डमैन सैक्स और वर्डे पार्टनर्स मददगार साबित हुई हैं
- गोल्डमैन सैक्स और वर्डे पार्टनर्स परियोजना के कुल कर्ज का 4,050 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे
- अमरावती परियोजना से 12 ऋणदाता जुड़े हुए थे जिनमें एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, ऐक्सिस बैंक मुख्य रूप से शामिल हैं

रिजर्व बैंक ने बॉन्ड बेचे और खरीदे मगर बढ़ गया प्रतिफल

अनूप रॉय
मुंबई, 30 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को द्वितीयक बाजार से 10,000 करोड़ रुपये के 10 वर्षीय बॉन्ड की खरीद की, वहीं अल्पावधि वाले 8,501 करोड़ रुपये के बॉन्डों की बिकवाली की। आरबीआई की यह कवायद इस कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार विशेष ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) के जरिए हुई।

ओएमओ के बाद दिलचस्प रूप से 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल कम होने के बजाय 5 आधार अंक चढ़कर 6.55 फीसदी पर बंद हुआ। ऐसे ओएमओ का मकसद लंबी अवधि का प्रतिफल नीचे लाना है और अल्पावधि का प्रतिफल बढ़ाना है। 10 वर्षीय प्रतिफल का कटऑफ 6.4874 फीसदी पर आने के बावजूद प्रतिफल में बढ़ोतरी हो रही है। अल्पावधि में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों (तीन साल) का कटऑफ प्रतिफल 5.39 फीसदी से 5.51 फीसदी के बीच रहा। आरबीआई ने कोई विशेष प्रतिभूतियां न बेचने का फैसला लिया है, शायद इसकी वजह बाजार की तरफ से कम प्रतिफल की पेशकश है।

एक बैंक के ट्रेजरी प्रमुख ने कहा, ओएमओ के बाद राज्य सरकारों की नीलामी का कैलेंडर सामने आया। इससे पता चला कि राज्य अगले तीन महीने में 25,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी लेंगे। इससे बाजार में ऐसा देखने को मिला।

पिछले हफ्ते आरबीआई ने 10 साल के बॉन्ड का पूरा कोटा खरीद लिया था, लेकिन अगले साल परिपक्व होने वाले महज 6,825 करोड़ रुपये को बॉन्डों की बिकवाली की।

एक वरिष्ठ बॉन्ड डीलर के मुताबिक, ओएमओ के बाद पप्रतिफल में बढ़ोतरी फंडामेंटल को प्रतिबिंबित करने के लिए हुई है और यह वास्तविकता बताने के लिए भी कि जब स्पष्ट तौर पर वित्त वर्ष के आखिर से पहले 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी का डर हो तो प्रतिफल ज्यादा होना चाहिए।

बॉन्ड डीलर ने कहा, ओएमओ की घोषणा से प्रतिफल 6.75 फीसदी से घटकर 6.55 फीसदी पर आ गया। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रतिफल और नीचे जाएगा क्योंकि आरबीआई ने दिसंबर में अपने कदम रोक लिए थे।

अगर और ओएमओ का ऐलान होता है तो बॉन्ड प्रतिफल में अस्थायी गिरावट आ सकती है। कीमतें बढ़ने पर प्रतिफल घटता है। कम प्रतिफल से सरकार को सस्ती उधारी में मदद मिलती है।

बॉन्ड का प्रतिफल

- ओएमओ के बाद दिलचस्प रूप से 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल कम होने के बजाय 5 आधार अंक चढ़कर 6.55 फीसदी पर बंद हुआ
- ऐसे ओएमओ का मकसद लंबी अवधि का प्रतिफल नीचे लाना है और अल्पावधि का प्रतिफल बढ़ाना है

म्युचुअल फंडों के एनएफओ में आई कमी

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 30 दिसंबर

इक्विटी और डेट फंड की नई पेशकश से संग्रह इस साल काफी ज्यादा घटा है क्योंकि अग्रिम कमीशन पर पाबंदी, इक्विटी बाजार की अनिश्चितता आदि के कारण नई पेशकश सीमित रही और इस कारण निवेश भी सीमित रहा।

मुख्य सूचकांक इस साल अब तक करीब 15 फीसदी चढ़े हैं, जिसकी अगुआई चुनिंदा शेयरों में बढ़त ने की। ध्रुवीकरण और मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों के कमजोर प्रदर्शन के कारण डायवर्सिफाइड इक्विटी योजनाओं ने खास तौर से बेहतर नहीं किया है। प्लान रुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, बाजार सहायक नहीं रहा है और कुछ चुनिंदा शेयर की चढ़े हैं। इसके परिणामस्वरूप एक साल और दो साल के एसआईपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। अगर मौजूदा पोर्टफोलियो लाल निशान में रहता है तो निवेशक नई रकम लगाने से पहले देखो व इंतजार करो की रणनीति अपना सकते हैं।

ट्रैक रिकॉर्ड के अभाव ने नई पेशकश में कुछ को बिक्री में मदद की है, जो कई मौजूदा योजनाओं के कमजोर प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में हुआ है। बाजार नियामक ने अग्रिम कमीशन पर पाबंदी लगाई है और प्रत्यक्ष या नकद या किसी वस्तु या किसी अन्य जरिये से निवेश के हिसाब से अग्रिम कमीशन पर रोक लगाई है। इस आदेश ने नई पेशकश पर असर डाला है, खास तौर से क्लोज ऐंडेड योजनाओं पर, जहां दिया जाने वाला कमीशन मोटे तौर पहले 5-6 फीसदी होता था।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादातर फंड हाउस अपनी योजनाओं के पोर्टफोलियो की खाई पाटने के लिए एनएफओ की पेशकश कर रहे हैं, न कि राजस्व अर्जित करने के लिए। वितरक को जहां निवेश के हिसाब से ज्यादा कमीशन के जरिए फायदा हो रहा है, वहीं प्रोत्साहन कम है क्योंकि कोई अग्रिम कमीशन नहीं दिया जा रहा।

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इंडिया के पोर्टफोलियो विशेषज्ञ धवल कापड़िया ने कहा, निवेश के हिसाब से कमीशन भुगतान का मॉडल अपनाने से फंड हाउस की तरफ से रकम जुटाने पर असर पड़ा होगा। साथ ही क्लोज ऐंडेड फंड पारंपरिक रूप से मिडकैप व स्मॉलकैप क्षेत्र में पेश किए गए। मिडकैप व स्मॉलकैप में इस साल गिरावट आई है, जिससे ऐसी पेशकश के सेंटिमेंट पर असर पड़ा है। नई इक्विटी पेशकश पर सेबी के एक योजना प्रति श्रेणी के आदेश का असर पड़ा है, जो पिछले साल लागू हुआ।

खास तौर से छोटे व मझोले फंड हाउस पिछले साल से अपना प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो पूरा करने के लिए योजनाएं पेश कर रहे हैं। सेबी ने मोटे तौर पर सभी इक्विटी योजनाओं को 10 श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड्स, सेक्टर/थिमेटिक फंडों की संख्या पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, जिसे पेश किया जा सकता है। कापड़िया ने कहा, ज्यादातर एएमसी के पास अब विभिन्न श्रेणियों के फंड हैं। जब प्रॉडक्ट बास्केट भर जाता है तो आप नियामक की तरफ से वर्गीकृत किसी प्रमुख श्रेणियों में कोई और फंड पेश नहीं कर सकते।

डेट की तरफ प्रॉडक्ट की पेशकश पर जोखिम का असर पड़ा है, जो आईएलऐंडएफएस घटनाक्रम के चलते है। उदाहरण के लिए फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान की पेशकश पर इसलिए पड़ा क्योंकि निवेशक लंबी अवधि तक अपनी रकम फंसाए नहीं रखना चाहते और वे रिटर्न के मुकाबले सुरक्षा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।

जोशी ने कहा, कुछ एफएमपी ने समय पर रकम वापस नहीं की या कुछ घटनाक्रम के कारण उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दिया। इससे उसका आकर्षण घटा है। इस साल एनएफओ संग्रह में मजबूती भारत 22 ईटीएफ की दो चरणों में पेशकश और हाल में संपन्न भारत बॉन्ड ईटीएफ, देश के पहले कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ से मिली।

सामान्य तौर पर वित्तीय सलाहकार एनएफओ में निवेश की वकालत नहीं करते क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं आते। एनएफओ में निवेश तब करना ठीक होता है जब तक विशाखित पेशकश हो और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो।

न्यू फंड ऑफर (एनएफओ)

इक्विटी व डेट फंड के जरिए इस साल जुटाई गई कम रकम

साल	इक्विटी		डेट	
	संख्या	कुल संग्रह	संख्या	कुल संग्रह
2013	28	2,757	878	1,16,257
2014	82	15,186	846	99,121
2015	71	7,783	270	23,159
2016	29	2,279	248	24,533
2017	64	36,641	225	16,443
2018	71	20,022	568	96,214
2019	52	8,137	262	22,069

स्रोत : वैल्यू रिसर्च। आंकड़े : करोड़ रुपये में

लीवरेज एजु ने जुटाए 15 लाख डॉलर

युवराज मलिक
बेंगलूरु, 30 दिसंबर

कॉलेज नामांकन से संबंधित परामर्श एवं कैरियर प्लेटफॉर्म लीवरेज एजु ने डीएसजी कंज्यूमर पार्टनर्स और ब्लूम वेंचर्स जैसे निवेशकों से 15 लाख डॉलर की पूंजी जुटाई है। सामा कैपिटल के संस्थापक ऐश लीलानी और पेयू इंडिया के पूर्व मुख्य कार्याधिकारी अमरीश राउ ने भी इस निवेश दौर में भागीदारी की है। डीएसजी कंज्यूमर और ब्लूम ने इस साल जनवरी में दो साल पुराने इस स्टार्ट-अप में 13 लाख डॉलर का निवेश किया था। डीएसजी कंज्यूमर के प्रबंध निदेशक दीपक शाहदादपुरी ने कहा, 'संक्षिप्त अवधि में अक्षय चतुर्वेदी और उनकी टीम ने मजबूत क्रियान्वयन क्षमताओं का प्रदर्शन किया और लीवरेज को प्रमुख उच्च शिक्षा एवं करियर परामर्श ब्रांड के तौर पर खास पहचान दिलाई।' लीवरेज की स्थापना वर्ष 2017 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के पूर्व छात्र अक्षय चतुर्वेदी ने की थी।

सुस्त ग्रामीण बिक्री से एफएमसीजी पर दबाव

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर

नोटबंदी और जीएसटी क्रियान्वयन के लगभग दो वर्ष बाद देश के उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र को 2019 से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन यदि पिछले 12 महीनों के उपभोक्ता बाजार पर नजर डालें तो नकारात्मक तस्वीर सामने आती है। जहां स्मार्टफोन और एयर कंडीशनर जैसे खास सेगमेंट को कुछ राहत मिली, वहीं एफएमसीजी को 2019 में भारी दबाव से जूझना पड़ा।

देश के 4 लाख करोड़ रुपये के एफएमसीजी बाजार (दुनिया में चौथा सबसे बड़े) को ग्रामीण इलाकों में समस्याओं के बीच सितंबर तिमाही में बिक्री घटकर सात वर्ष के निचले स्तर पर रह जाने से कड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ा। बाजार विश्लेषक फर्म नीलसेन से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण बाजार में बिक्री वृद्धि तिमाही के दौरान घटकर महज 2 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले 16 प्रतिशत थी। सात वर्षों में यह पहली बार था जब ग्रामीण बाजार में वृद्धि शहरी की तुलना में नीचे आ गई।

जाड़े के महीनों की मंदी के बाद पारंपरिक तौर पर मजबूत अवधि समझी जाने वाली अप्रैल-जून तिमाही में ग्रामीण बाजारों में वृद्धि 2018 की शुरुआत के बाद से सबसे कमजोर रही। नीलसेन के अनुसार, फूड और पर्सनल केयर श्रेणियां मंदी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित

हुईं। एजेंसी के अनुसार जहां कैलेंडर वर्ष 2018 में फूड एवं पर्सनल केयर की वैल्यू वृद्धि 15 और 12 प्रतिशत रही, वहीं 2019 में यह घटकर 12 प्रतिशत और 11 प्रतिशत रह गई।

कई एफएमसीजी कंपनियों के लिए 2018 के मध्य तक ग्रामीण इलाकों में बिक्री वृद्धि शहरी बिक्री वृद्धि की तुलना में कम से कम 4 से 7 प्रतिशत तक ज्यादा थी।

2019 में भारत की कुल आर्थिक वृद्धि धीमी रही और शहरी बाजार में भी इसी तरह का रुझान देखा गया जिससे एफएमसीजी निर्माताओं की चिंता बढ़ गई। शहरी इलाकों में बिक्री वृद्धि सितंबर में घटकर 5 प्रतिशत रह गई जो 2018 की समान अवधि में 11 प्रतिशत थी। इस बीच, भारत की जीडीपी में वृद्धि एक साल पहले के 7 प्रतिशत और जुलाई-सितंबर 2016 के 8.9 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2019 में 4.5 प्रतिशत रह गई।

नेस्ले से लेकर एचयूएल जैसी बड़ी एफएमसीजी कंपनियों को दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि उपभोक्ताओं ने खरीदारी करने से काफी हद तक परहेज किया। देश की सबसे बड़ी नॉन-सिगरेट एफएमसीजी कंपनी एचयूएल के मुख्य कार्याधिकारी संजीव मेहता ने कहा कि बड़ी गिरावट ग्रामीण इलाकों में मंदी की वजह से आई।

एडलवाइस सिक्योरिटीज के शोध के अनुसार, दो प्रमुख कारकों का 2019 में एफएमसीजी कंपनियों पर प्रभाव पड़ा। पहला, वृहद आर्थिक समस्याओं से खासकर ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता धारणा प्रभावित हुआ। दूसरा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जुड़ा नकदी संकट बरकरार रहने से थोक और खुदरा स्तरों पर मांग प्रभावित हुई।

इसके अलावा वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान दूध, गेहूं और चीनी जैसी कृषि-आधारित जिंसों के महंगा होने से एफएमसीजी कंपनियों का मार्जिन प्रभावित हुआ। एडलवाइस की रिपोर्ट में कहा गया है, 'इससे नेस्ले का सकल मार्जिन सालाना आधार पर 216 आधार अंक तक घटा और ब्रिटानिया का सकल मार्जिन सपाट बना रहा।' हालांकि स्मार्टफोन और खास ड्यूरेबल श्रेणियों जैसे उपभोक्ता वस्तु खंडों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए, 2019 में एयर कंडीशनर की बिक्री में सुधार देखा गया। 2017 और 2018 में ऊंचे करों, रुपये में कमजोरी और जिंस कीमतों में तेजी की वजह से एयर कंडीशनर की बिक्री में कमी आई थी।

रेलवे का लक्ष्य निगमीकरण, निजीकरण नहीं

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 30 दिसंबर

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने आज कहा कि सरकार उत्पादन इकाइयों, रेल के बुनियादी ढांचे या रेल के परिचालन के निजीकरण की कोई योजना नहीं बना रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उम्मीद की जा रही है कि रेलवे अगले 15 दिन में यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए बोली आमंत्रित करेगा, लेकिन मालिकाना सरकार के पास बना रहेगा।

उन्होंने कहा, 'हम किसी भी हिस्से या रेलवे की उत्पादन इकाई के निजीकरण की योजना नहीं बना रहे हैं। इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं।'

वहीं दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड ने अपनी सहायक इकाई आरआईटीईएस से कहा है कि वह अपनी उत्पादन इकाइयों के कॉर्पोरेटीकरण के लिए रिपोर्ट तैयार करे। योजना के मुताबिक रेलवे अपनी सभी उत्पादन इकाइयों और उनसे जुड़े वर्कशॉप से अलग होगा और इसके लिए एक नई सरकारी इकाई इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी बनेगी।

यादव ने कहा कि कर्मचारियों से बातचीत के बाद ही यह कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, 'विशेष निर्देश दिए गए हैं कि मौजूदा कर्मचारियों को किस तरह से समायोजित किया जाए, जिससे कि उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो। इसे निजीकरण की ओर बढ़े कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।'

वहीं दूसरी ओर खबरों में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड कम से कम 150 ट्रेनें चलाने के लिए निजी कारोबारियों को आमंत्रित कर सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने कहा कि अगले 15 दिन में बोली आमंत्रित की जा सकती है।

यादव ने कहा, 'निजी ट्रेन ऑपरेटरों को यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिए लाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बुनियादी ढांचा, रखरखाव और सुरक्षा का काम पूरी तरह से भारतीय रेलवे के हाथों में रहेगा।' निजी कारोबारी दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख मार्गों पर रेल परिचालन का काम ट्रैक के नवीकरण के बाद करेंगे। नवीकरण में चहारदीवारी बनाना, नई सिगनल व्यवस्था और समर्पित मालवहन गलियारों (एडीएफसी) का काम शामिल है। डीएफसी पेश किए जाने के बाद मौजूदा मार्गों के उन्नयन का काम पूरी तरह से यात्री ट्रेनों के लिए समर्पित होगा।

यादव ने कहा कि वित्त की मौजूदा कमी से रेलवे को ज्यादा कार्यकुशल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान परिचालन मुनाफा 121 प्रतिशत रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 113 प्रतिशत की तुलना में बहुत नीचे है। परिचालन में वह राशि होती है, जो रेलवे प्रति रुपये कमाई पर खर्च करता है, जिसका मतलब हुआ कि कम परिचालन अनुपात होने से वित्तीय स्थिति बेहतर रहती है।

चेयरमैन ने कहा, 'हमें वित्तीय समस्या है। यह सहायक भी है क्योंकि हम ज्यादा कुशल बन सकते हैं। सेवाओं के एकीकरण का हाल का फैसला इनमें से एक कदम है, जिससे तेजी से फैसले करके कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है।' यादव ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना प्रमुख वजह है, जिससे परिचालन अनुपात बढ़ा है। रेलवे की कमाई का करीब 65 प्रतिशत कर्मचारियों पर खर्च होता है, जिसमें 12 लाख कर्मचारी और 13 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि यात्री किराये में बढ़ोतरी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, वहीं दूसरी तरफ माल भाड़े में बढ़ोतरी रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

रेलवे का निजीकरण नहीं

विनोद कुमार यादव, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड

15 दिन में यात्री रेल के परिचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए बोली आमंत्रित की जाएगी

150 ट्रेनें निजी क्षेत्र को चलाने के लिए देने की तैयारी

- रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि यात्रियों को सुविधा देने के लिए निजी क्षेत्र को परिचालन देने की योजना है

मजबूत रहा वाणिज्यिक रियल एस्टेट, हाउसिंग बाजार नीचे

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 30 दिसंबर

आवासीय रियल एस्सेट के लिए 2019 कठिन वर्षों में से एक रहा है। लंबी चली मंदी, लगातार नकदी संकट, दिवाला मामले आदि जैसी समस्याएं बनी रहीं। इसकी तुलना में वाणिज्यिक रियल एस्टेट की स्थिति अच्छी रही और कुल कारोबार व किराये में बढ़ोतरी देखी गई।

सलाहकारों व डेवलपरों का कहना है कि अगला साल भी होम डेवलपरों के लिए खराब साबित होने की संभावना है। उनके मुताबिक कीमतें स्थिर रहेंगी और बिक्री में बहुत धीमी बढ़ोतरी होगी।

बहरहाल इस दौरान ब्रांडेड डेवलपरों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने बेहतीन ब्रांड, सही मूल्य और बेहतर जगहों पर परियोजनाएं पेश कीं। उन्हें उम्मीद है कि नया साल भी बेहतर रहेगा।

2019 में लोखंडवाला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स दिवालिया हो गई। एचडीआईएल के प्रवर्तक सारंग और राकेश वधावन पीएमसी बैंक घोटाले में गिरफ्तार किए गए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले साल में और डेवलपर दीवालिया होंगे।

तमाम हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों (एचएफसी) ने कर्ज देना बंद कर दिया है, डीएचएफएस उनमें से एक है। तमाम और ने भी उधारी लेने वालों का भुगतान रोक दिया है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में संकट आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी हाल की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में रियल एस्टेट क्षेत्र में दबाव का उल्लेख किया है। इसमें कर्जदाताओं को होने वाले नुकसान का जिक्र किया गया है। एचएफसी, सार्वजनिक व निजी बैंकों क्रेडिट नुकसान जून 2019 में बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गया, जो जून 2018 में 5.7 प्रतिशत था।

आवास

एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के मुताबिक आवासीय रिलय एस्टेट में 2019 में 4 से 5 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर्ज हुई और साल में करीब 2,58,000 मकान बेचे गए। इसमें कहा गया है कि 2019-20 में नई पेशकश में सालाना 18 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो 2,30,000 यूनिट से थोड़ी ज्यादा है। सस्ते आवास क्षेत्र में करीब 22 प्रतिशत आपूर्ति हुई है। प्रमुख 7 शहरों में कुल 2,61,000 यूनिट की बिक्री हुई है, जो कुल बिक्री का 38 प्रतिशत है।

जेएलएल में मुख्य अर्थशास्त्री सामंतक दास ने कहा, 'हमें नहीं लगता कि प्राथमिक आवासीय बाजार पर कोई दबाव होगा और अभी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होने में एक साल और लगेंगे। तब तक वृद्धि दर में मामूली बढ़ोतरी होगी या हो सकता है कि 2018 जैसी स्थिति ही रहे।'

इस क्षेत्र में तेजी के लिए केंद्र सरकार ने कई कदमों की घोषणा की है, खासकर सस्ते आवास क्षेत्र के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि कुल मिलाकर बिक्री में तेजी नहीं आ रही है। 2019-20 के केंद्रीय बजट में सरकार ने कर्ज लेने वालों को ब्याज पर 1,50,000 रुपये छूट देने की घोषणआ की, जो 31 मार्च 2020 तक मिलेगी। यह 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों को मिलनी है। इसके अलावा सस्ते आवास पर वस्तु एवं सेवा कर घटाकर1 प्रतिशत करने व अन्य श्रेणियों पर 5 प्रतिशत कर करने की घोषणा की गई।

सरकार ने रुकी हुई परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष भी बनाया है।

कार्यालय बाजार

सीबीआरई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस लीजिंग 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर पहली तीन तिमाही में 4.7 करोड़ वर्गफुट हो गई, जो 2018 के शीर्ष स्तर से ज्यादा है। जेएलएल के दास ने कहा, 'को-वर्किंग सेग्मेंट ने वैश्विक रूप से कुछ व्यवधान पैदा किया है। लेकिन आपूर्ति के हिसाब से कुछ छोटे शहरों का प्रदर्शन बेहतर रहा है।'

हैदराबाद एक उदारहण है, जहां जेएलएल के मुताबिक बेंगलूरु की तुलना में बराबर आपूर्ति रही है, जबकि बेंगलूरू देश का सबसे बढ़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि ऐसे में बहुत कम अवधि के दौरान हम हैदराबाद जैसे शहरों में रिक्तियों में कुछ बढ़ोतरी देख सकते हैं, जहां आपूर्ति बड़ी मात्रा में होने जा रही है।

एनरॉक के मुताबिक 2019 की पहली तीन तिमाही में सभी श्रेणी के रियल एस्टेट में वाणिज्यिक जगहों ने सबसे ज्यादा निजी इक्विटी निवेश आकर्षित किया है। यह 3 अरब डॉलर (21,400 करोड़ रुपये) रहा। 2018 में इसी अवधि के दौरान इस क्षेत्र में कुल प्रवाह करीब 2.1 अरब डॉलर था और इस तरह से इसमें 43 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

ब्रिटेन की सलाहकार संस्था नाइट फ्रैंक ने हाल ही में कहा कि बेंगलूरु और मुंबई सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) में 2020 के दौरान कार्यालय का किराया बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें सूचना तकनीक क्षेत्र की भूमिका अहम रहेगी। तीसरी तिमाही के दौरान बेंगलूरु का सीबीडी एशिया प्रशांत के बाजारों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला रहा, जहां नाइट फ्रैंक एशिया पैसिफिक प्राइम ऑफिस रेंटल इंडेक्स के मुताबिक किराये में 17.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस और मुंबई के बीकेसी एशिया प्रशांत के तेजी से बढ़ते प्रमुख कार्यालय बाजारों में क्रमश: 7वें और 11वें स्थान पर रहे।

ब्लैकस्टोन और उसके साझेदार एंबेसी ने इतिहास बनाया, जब उन्होंने देश के पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) को सूचीबद्ध कराया। एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, '2020 में और ज्यादा वाणिज्यिक डेवलपर आरईआईटी को सूचीबद्ध कराएंगे और पूंजी जुटाने के लिए अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कराएंगे।'

खुदरा

हालांकि खुदरा संपत्तियों के पट्टे पर आर्थिक मंदी का असर पड़ा है, वहीं मॉल डेवलपर प्रेस्टिज इस्टेट, वर्चुअस रिटेल साउथ एशिया और इनऑर्बिट को उम्मीद है कि अगले एक या दो साल में संगठित खुदरा की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

कुल मिलाकर खुदरा लीजिंग गतिविधियां प्रमुख 7 शहरों में 35 प्रतिशत कम हुई हैं और 2018 के 55 लाख वर्गफुट की तुलना में 2019 में यह 36 लाख वर्गफुट रह गया है। एनरॉक के अनुज पुरी ने कहा, 'संगठित खुदरा की हिस्सेदारी 2019 में बढ़ी है। हालांकि कुल

कैसा रहा साल 2019

- आवासीय डेवलपरों की लंबी चली मंदी, लगातार नकदी संकट, दिवाला मामले आदि जैसी समस्याएं रहीं
- इस दौरान ब्रांडेड डेवलपरों का प्रदर्शन बेहतर रहा
- वाणिज्यिक रियल एस्टेट की स्थिति अच्छी रही और कुल कारोबार व किराये में बढ़ोतरी हुई
- सलाहकारों व डेवलपरों का कहना है कि होम डेवलपरों के लिए अगला साल भी खराब रहने जा रहा है
- कीमतें स्थिर बनी रहने की संभावना और बिक्री में मामूली बढ़ोतरी संभव

टिकाऊ विकास के लक्ष्यों में शीर्ष पर केरल : नीति आयोग

नीति आयोग की ओर से तैयार की गई इस साल की रैंकिंग में टिकाऊ विकास के लक्ष्यों में केरल शीर्ष पर है। केरल शीर्ष पर बना हुआ है, वहीं 2018 में शीर्ष रैंकिंग साझा करने वाला हिमाचल प्रदेश इस साल की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस साल के टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के सूचकांक में बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम ने सबसे ज्यादा सुधार दर्ज किया है, वहीं 2018 की रैंकिंग की तुलना में गुजरात जैसे राज्यों में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत का कुल स्कोल 2018 के 57 से सुधरकर 2019 में 60 हो गया है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से एसडीजी भारत सूचकांक पिछले साल जारी किया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी के 17 क्षेत्रों में से 16 को रखा गया है। इस साल का सूचकांक राज्यों को 100 संकेतकों पर आधारित 54 लक्ष्यों के मामले में प्रगति के आधार पर तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे 306 संकेतकों की पहचान की है। 2018 में जारी पहली रिपोर्ट में 13 लक्ष्य और 39 संकेतक थे। *इंदिवजल धस्माना*

नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए टिकाऊ विकास लक्ष्यों में राज्यों की रैंकिंग

रैंक	2018	2019
1	केरल और हिमाचल प्रदेश	केरल
2	तमिलनाडु	हिमाचल प्रदेश
3	आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना
4	तेलंगाना	कर्नाटक
5	पंजाब और उत्तराखंड	सिक्किम और गोवा

"संयुक्त राष्ट्र का 2030 का एसडीजी लक्ष्य भारत के बिना कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। हम स्वस्थ विकास के संयुक्त राष्ट्र में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं

अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग

एमएसई क्षेत्र में निराशा की रिपोर्ट

अभिजित लेले
मुंबई, 30 दिसंबर

लंबे समय से चल रही आर्थिक गिरावट की वजह से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की कारोबारी धारणा तेजी से गिरकर सितंबर 2019 तिमाही में 106 पर पहुंच गई है, जो अप्रैल जून 2019 तिमाही में 120 थी। क्रिसिल-सिडबी सर्वे (क्रिसिडेक्स) में यह सामने आया है।

जनवरी-मार्च 2019 में सूचकांक की रीडिंग 122 और अक्टूबर-दिसंबर में 128, जुलाई-सितंबर 2018 में 124 थी। क्रिसिल के मुख्य परिचालन अधिकारी अमीश मेहता ने कहा कि सितंबर 2019 तिमाही के आंकड़ों से पता चलता है कि व्यापक आर्थिक वजहों के हिसाब से विचार करने की जरूरत है, जिसमें ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन में कटौती शामिल है, जिससे इसके कल पुर्जों का उपयोग प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि जिंस से जुड़े क्षेत्रों जैसे स्टील में मात्रा व रियलाइजेशन दोनों में गिरावट आई है और मंदी की वजह से रत्न एवं आभूषण और होटलों में खपत घटी है।

सर्वे में कहा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2019 की उम्मीदें वास्तविक धारणा से कहीं बेहतर थीं। दिसंबर 2019 तिमाही की रीडिंग 129 और वास्तविक रीडिंग 106 में भारी अंतर है।

क्रिसिडेक्स की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई

- एमएसई की कारोबारी धारणा सितंबर 2019 तिमाही में 106 पर पहुंच गई है, जो अप्रैल जून 2019 तिमाही में 120 थी
- व्यापक आर्थिक वजहों जैसे वाहन उत्पादन में कटौती की वजह से हुआ कल पुर्जा विनिर्माताओं का बुरा हाल
- कर्जदाता भी मान रहे हैं कि कारोबार की स्थिति है खराब
- अगली तिमाही को लेकर भी सकारात्मक रुख नहीं

उत्पादन और क्षमता उपयोग अगली तिमाही में स्थिर बने रहने की उम्मीद है। विनिर्माण एमएसई से जुड़े सर्वे में शामिल 28 प्रतिशत लोगों ने उम्मीद जताई कि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी जबकि 65 प्रतिशत ने कहा कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगाक। वहीं 7 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उत्पादन कम रहेगा।

नई नौकरियों में स्थिरता रही। सिर्फ 7 प्रतिशत एमएसई ने कहा कि एसक्यू8 में उन्होंने कर्मचारी बढ़ाए हैं, जबकि एसक्यू7 में 16 प्रतिशत ने कर्मचारी बढ़ाने की बात कही थी। वहीं 87 प्रतिशत ने कहा कि पहले जितने कर्मचारी बरकरार हैं जबकि 6 प्रतिशत ने कर्मचारी कम किए जाने की बात कही है।

कर्जदाताओं की धारणा कारोबार की स्थिति को लेकर नकारात्मक रही। सितंबर तिमाही में 10 में से सिर्फ 1 कर्जदाता ने सर्वे में कहा कि कुल मिलाकर कारोबारी स्थिति में सुधार की बात कही, जबकि 10 में से 4 ने स्थिति को संतोषजनक बताया और 10 में से 5 ने कहा कि स्थिति संतोषजनक स्थिति से नीचे है।

एसबीआई के मानक ब्याज में कमी

एजेंसियां
नई दिल्ली, 30 दिसंबर

देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज कर्ज के लिए बाह्य मानकों पर आधारित अपनी ब्याज दर (ईबीआर) को 0.25 प्रतिशत कम कर 7.80 प्रतिशत करने की घोषणा की। अभी यह दर 8.05 प्रतिशत थी।

नई दर पहली जनवरी 2020 से प्रभावी होगी। बैंक के इस निर्णय से उसके आवास ऋण पर ब्याज कम हो जाएगा और उससे ईबीआर के आधार पर कर्ज लेने वाले सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों पर भी ब्याज के बोझ में प्रति सैकड़ा 25 पैसे की कमी हो जाएगी। बैंक नए आवास ऋण वार्षिक 7.90 प्रतिशत की दर से पेश करेगा। अब तक यह दर 8.15 प्रतिशत थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने पहली अक्टूबर 2019 से ईबीआर आधारित ब्याज की व्यवस्था लागू की है। बैंक ने इसके तहत 1 अक्टूबर 2016 से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों, आवास खरीदारों तथा खुदरा ग्राहकों के लिए परिवर्तनशील दर पर लिए गए कर्जों का ब्याज रिजर्व बैंक की रीपो दर (जिस दर पर वह बैंकों को फौरी जरूरत के लिए नकद धन देता है) में घट बढ़ के आधार पर समायोजित करने का निर्णय लागू किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष फरवरी से कुल मिला कर रीपो दर 1.35 प्रतिशत कम की है। लेकिन बैंक उसका लाभ ग्राहकों को देने में धीमे रहे हैं। उनकी ओर से ब्याज में औसतन 0.44 प्रतिशत की ही कटौती की गई है। बैंकों को बाह्य मानकों के आधार पर हर तीन महीने में ब्याज दरों में बदलाव की अनुमति है।

मिली राहत

- एसबीआई की बाह्य मानकों पर आधारित ब्याज दर **0.25** प्रतिशत घटी
- नई दर **1** जनवरी से लागू, जिससे आवास ऋण पर ब्याज कम होगा
- अब बैंक **8.15** प्रतिशत की जगह **7.90** प्रतिशत ब्याज पर देगा आवास ऋण

मिल सकती है सीलिंग से राहत

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 30 दिसंबर

दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली के कारोबारियों को सीलिंग से राहत देने के साथ ही उनकी अन्य समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। दिल्ली भाजपा ने आज व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में दिल्ली के कारोबारियों ने सील हो चुकी 8000 से अधिक दुकानों की सील खोलने और आगे सीलिंग से निजात दिलानी मांग की।

कारोबारियों की मांग पर केंद्रीय शहरी विकास व आवास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली के कारोबारियों को कई क्षेत्रों में सीलिंग से राहत दिलाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किए हैं। सील हो चुकी दुकानों की सील खोलने और आगे सीलिंग से पूरी तरह छुटकारा दिलाने की मांग पर पुरी ने कहा कि सीलिंग उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हो रही है। इसलिए केंद्र सरकार कानूनी रास्ता अपनाकर इस समस्या का समाधान करेगी।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने कारोबारियों के हित में कारोबारी पेंशन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड जैसे अनेक फैसले लिए हैं और सरकार दिल्ली के कारोबारियों की समस्याओं का भी समाधान करेगी।

वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के कारोबारी भाजपा शासित नगर निगम की सीलिंग से दुखी हैं। भाजपा को सीलिंग बंद करने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर कारोबारियों को धोखा देने का आरोप लगाया।

- केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का व्यापारी सम्मेलन में कारोबारियों को सीलिंग खत्म करने का आश्वासन
- कारोबारियों ने की सील हो चुकी दुकानों की सील खोलने की मांग
- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वादा कारोबारियों की समस्याओं को होगा समाधान

बीएस सूडोकू 3626 | परिणाम संख्या 3625

5		6		8	2		1	
		8			6		3	
			4	5				8
2	9		1		5	4		
8		5				3		1
		3	8		4		2	5
9				6	8			
	3		2			8		
	8		5	4		2		9

5	9	4	3	8	6	2	1	7
8	6	7	1	5	2	3	4	9
1	3	2	4	9	7	5	6	8
2	7	1	8	6	5	4	9	3
9	8	5	7	4	3	6	2	1
6	4	3	9	2	1	8	7	5
4	5	9	2	1	8	7	3	6
3	1	8	6	7	4	9	5	2
7	2	6	5	3	9	1	8	4

कैसे खेलें? हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान ★ ☆ ☆ ☆ ☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2165/2175, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4575/4600, तिल सफेद 9500/9700, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1650/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2200/2210, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1455, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1535, फ्लैक 1470, डीएमओ 1065, टरपीन लैस बोल्ड 1565

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1350/1410, खुरपा 1250/1300,चाकू 1225/1310, रसकट 1000/1020, शक्कर 1400/1435, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3385, सिहोरा 3255, बुंदकी 3290,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1300/1350, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4650, खल: सरसों 2350/2450, बिनौला 2550/2700, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2220/2225, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3900/3950, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4820/4825,

श्रीगंगानगर
गेहूं (देरी) 2100/2125, ग्वार 3950/4000, जौ 2190/2200,

जोधपुर
गेहूं 2100/2125, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4150/4200, ग्वारगम 7800/7900, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4250/4400, काबली चना 5000/6000, मूंग 6500/6700,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्याइंट)131, राइसब्रान (अखाद्य) 128, खल सरसों 2100, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1350,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8500/9500, दाल मसूर 5800/6200, चनादाल 5300/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5550/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4150/4250,चावल 1509 सेला 5150/5250, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4045/4075, हरियाणा 4040/4050, राजस्थान 3960/4050, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2600/2700, सरसों खल 2240/2250,

फाजिल्का
गेहूं 2230/2240, सरसों 4500/4625 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4075, कपास देशी 5050/5150, कपास नरमा (क्विं.) 5350/5500, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2700/2750,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2240/2250, चावल परमल कच्चा 2500/2550, से ला 2400/2425, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2500/2525, दाल उड़द छिलका 9200/10900, चना देशी 5200/5300, दाल चना 5500/5700, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7000/8400, चीन 7500/8100,

करनाल
गेहूं दड़ा 2210/2230, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 3850/3900, जौ 1775/1780, सरसों 4300/4400, मूंग 6500/6600, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1050/1070, मैदा 1150/1170, देशी घी (एक ली/जार) 380/480, रिफाइंड (टीन) 1510/1540,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4300/4350, खल बिनौला मोटी 2500/2600, बिनौला 2900/3400, सरसों तेल 9450/9500, गेहूं 2150/2200, ग्वार 3900/3950, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 270

डेटा विश्वसनीयता हो बहाल

यह एक स्वागतयोग्य खबर है कि पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन की अगुआई में एक उच्चस्तरीय पैनल बनाया गया है जो रोजगार, उद्योग एवं सेवाओं के फिलहाल होने वाले सर्वेक्षणों की पड़ताल करेगा। विभिन्न प्रमुख सरकारी आंकड़ों खासकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकलन में ये सर्वेक्षण जरूरी इनपुट होते हैं। इस 28 सदस्यीय समिति को यह काम सौंप दिया गया है। भारत के आधिकारिक आंकड़ों पर हाल में काफी सवाल उठे हैं। कई बार ये आंकड़े एक-दूसरे और अर्थव्यवस्था के अन्य संकेतकों के उलट मकसद से काम करते हैं। अधिक चिंताजनक बात यह है कि उनकी विश्वसनीयता और राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता भी हमले की जद में रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के हालिया दौर जैसे कुछ आंकड़ों को छिपाने के मामले में सरकार की इच्छा ने इन आशंकाओं को निर्मूल साबित करने में मदद नहीं की है। इस समिति के गठन के साथ ही डॉ सेन को इसका अध्यक्ष बनाने और हालिया आंकड़ों को संदेह की नजर से देखने वाले विद्वानों को इसमें शामिल करना भारत के आधिकारिक आंकड़ों की प्रतिष्ठा बहाल करने में थोड़ा मददगार हो सकता है।

हालांकि बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि पैनल खुद को कितना सशक्त महसूस करता है और कितनी पारदर्शिता से वह सांख्यिकीय प्रणाली को पुनर्गठित कर सकता है। समिति को विभिन्न सरकारी डेटा समूहों के परीक्षण के लिए कहा गया है। मसलन, उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों और श्रम शक्ति के सर्वेक्षणों के अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का परीक्षण यह समिति करेगी। समिति के दायरे के बाहर वही डेटा रखे जा सकते हैं जो लगातार स्थिर हैं और दूसरे के साथ तालमेल में हैं। माना जा रहा है कि समिति सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की निगरानी और प्रशासकीय आंकड़ों के संकलन में आने वाली समस्याओं को चिह्नित करने का भी काम करेगी।

इसका मतलब है कि अगर समिति चाहे तो उसके पास भारत के सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य को दुरुस्त करने की सापेक्षिक रूप से व्यापक शक्तियां हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकार निष्पक्ष विशेषज्ञों की राय स्वीकार करे। शासन के प्रति अज्ञेयवादी सांख्यिकीय प्रणाली के साथ बड़ी समस्याएं हैं और उन्हें दूर करने की जरूरत है। उपभोग सर्वेक्षण में दिखाए जा रहे और राष्ट्रीय खातों से उजागर खपत के बीच भिन्नता होना ऐसा ही एक मसला है। संभवत: औपचारिक क्षेत्र पर अधिक जोर देने वाली जीडीपी की गणना कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से करने का मुद्दा भी है। अपस्फीतिकारकों की गणना का तरीका और कॉर्पोरेट आंकड़ों को सही ढंग से अलग रखने का मुद्दा भी अहम होगा।

सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) के गठन की मंशा रखने वाले कानून का मसौदा जारी किया है जिसमें राष्ट्रीय आंकड़ों के लिए शीर्ष निकाय बनाने का प्रावधान है। माना जा सकता है कि संसद की आर्थिक सांख्यिकी समिति मसौदे पर चर्चा कर यह तय करेगी कि डेटा संग्रह एवं विश्लेषण पर भावी सुधारों का खाका बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? इन कदमों को लागू करने के लिए एनएससी जिम्मेदार होगा। हालांकि महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एक संस्था के तौर पर एनएससी को मजबूत बुनियाद और ताकत मिले। एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय होने के साथ ही आयोग के पास सरकारी स्तर पर संग्रहीत आंकड़ों के वितरण एवं उन्हें जारी करने पर निगरानी की शक्तियां भी होनी चाहिए। ऐसा होने पर यह संदेह नहीं रह जाएगा कि सरकार या उसके अफसर राजनीतिक कारणों से असुविधाजनक आंकड़ों को छिपा रहे हैं या उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। एनएससी विधेयक में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है।

अजय मोहंती

भारत के लिए अहम है सन 2020

वैश्विक निवेशकों को लंबी अवधि में भारत की तेजी का यकीन दिलाने के लिए शायद यह अंतिम वर्ष होगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **आकाश प्रकाश**

वर्ष 2019 का अंत करीब है और हम कह सकते हैं कि यह वर्ष एक बार फिर देश के सक्रिय फंड प्रबंधकों के लिए कठिन रहा है। बाजार का दायरा बहुत संकुचित रहा है और भले ही सूचकांक डॉलर के संदर्भ में 5-7 फीसदी का लाभ दर्शा रहे हों लेकिन हकीकत में भारत पर केंद्रित कई फंड गिरावट पर हैं। एक फंड आवंटक ने हाल ही में मुझसे कहा कि उन्होंने देश के फंडों के प्रदर्शन में ऐसी भिन्नता कभी नहीं देखी।

हम सन 2020 में प्रवेश कर रहे हैं और कई लोगों ने लंबी अवधि में भारत की तेजी को लेकर सवाल करने शुरू कर दिये हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और प्रति व्यक्ति अनुपात आज जिस स्तर पर है, चीन 2003-04 में उस स्तर पर था। किसी को यह अपेक्षा नहीं कि भारत चीन की तरह दो अंकों की वास्तविक जीडीपी भले हासिल न कर पाए लेकिन क्या 7 फीसदी की दर भी वास्तविक है? प्रशासनिक और न्यायिक अड़चनों को देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं।

वैश्विक निवेशक देश की वास्तविक वृद्धि के रुझान आंक रहे होंगे। क्या यह केवल 5-6 फीसदी है या हमारा देश 8 फीसदी की पुरानी दर की ओर वापसी कर सकता है? इससे निवेशकों के लिए बड़ा अंतर पैदा होगा। यदि भारत केवल 5 फीसदी की दर से वृद्धि हासिल कर सकता है तो यहां समय क्यों गंवाना? 5 फीसदी वास्तविक जीडीपी के साथ 9 फीसदी की नॉमिनल जीडीपी हासिल होगी और मंदड़िये कह सकते हैं कि लंबी अवधि के लिए भी यही दर होगी। दरअसल भारत का शेयर प्रतिफल केवल 10-11 फीसदी है। हां, कुछ अच्छी कंपनियां हैं लेकिन ज्यादातर पहले ही काफी ऊपर कारोबार कर रही हैं। इस लिहाज से देखें तो भारत ऊंची और स्थायी वृद्धि के लिए तैयार नहीं है। 2003-08 में हम भाग्यशाली थे। उस वक्त वैश्विक वृद्धि का माहौल नरम था।

पहले के सुधारों का भी लाभ मिल रहा था। हम दोबारा उस उच्च वृद्धि दर तक शायद ही लौट सकें।

उच्च वृद्धि के साथ आंकड़े स्वाभाविक रूप से अलग नजर आते हैं। 13 फीसदी की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि और कुछ वर्षों के लिए 30 फीसदी की मुनाफा वृद्धि की बात करें तो मुनाफा बढ़ने के साथ-साथ शेयर प्रतिफल भी बढ़ेगा। आय की इस धारा के लिए निवेशक भुगतान करने को तैयार हैं। इसलिए क्योंकि कोई अन्य बड़ा बाजार आने वाले पांच वर्ष में ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। वृद्धि की चुनौती से जूझ रही दुनिया में उच्च वृद्धि और बढ़ा हुआ शेयर प्रतिफल अत्यंत मूल्यवान है। इस उच्च वृद्धि परिदृश्य में जब देश की आबादी का तीसरा हिस्सा खपत करने लगेगा तो स्थायित्व और अनुमन्यता में भी सुधार होगा। निवेशक को कम स्थिर और अधिक अनुमान वाले बाजार में प्रीमियम चुकाएंगे।

निवेशक अभी भी निश्चित नहीं हैं कि देश में वृद्धि में यह कमी चक्रीय है या ढांचागत। अगले 12 महीनों में कई लोग लंबी अवधि का नजरिया कायम करेंगे। मंदी ने पहले ही सबको चौंका दिया है। उसकी अवधि के आकलन और कारणों का अनुमान लगाते हुए निवेशक लंबी अवधि के आवंटन पर निर्णय करेंगे।

सन 2020 वह वर्ष है जब आखिकार निवेशक मोदी सरकार के आर्थिक एजेंडे और नीति निर्माण की काबिलियत के बारे में नजरिया बनाएंगे। बीते पांच वर्ष के दौरान नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर, ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संकट आदि के रूप में एक के बाद एक झटके लगे। कारोबारी जगत में साफ-सफाई का भी एक सिलसिला चला। यह कहीं न कहीं तो समाप्त होगा। अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने का क्या अर्थ है? यह अर्थव्यवस्था के लिए कैसे बेहतर है? यदि कॉर्पोरेट आय इतने बुरे दौर से गुजरेगी तो अर्थव्यवस्था को औपचारिक कैसे बनाया जा सकेगा? क्या औपचारिक बनाने का अर्थ है छोटे उपक्रमों का समापन क्योंकि वे बदल नहीं सकते? क्या अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने से रोजगार जाएंगे?

जो लोग सोचते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण नहीं रहेगी उनके लिए आने वाला वर्ष अहम है। देश का नेतृत्व इस मंदी से कैसे निपटेगा?

सन 2020 दिखाएगा कि मोदी सरकार ढांचागत सुधारों को लेकर कितनी गंभीर है। देश गंभीर आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, यदि हम अब सुधारों को लेकर अहम कदम नहीं उठाए तो कब उठाएंगे? वैश्विक निवेशकों को पूरा यकीन है कि भारत के लिए सरकारी बैंकों में सुधार का यह बेहतरीन अवसर है। इसके अलावा प्रशासनिक बदलावों और देश को बेहतर कारोबारी केंद्र बनाने का भी यह अच्छा मौका है। इस सरकार के पास राजनैतिक ताकत है, एक शक्तिशाली नेता है जो अतीत में वृद्धि हासिल करने में सहायक रहा है और जिसने जोखिम उठाने का माद्दा दिखाया है। यदि यह सरकार अफसरशाही से काम नहीं ले सकती तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा।

भारत के लिए यह अवसर है कि वह वृद्धि को बढ़ावा देने वाले नये सुधार अपना सके। यदि हमने अब जोर नहीं दिया तो भविष्य में इसके पक्ष में दलील देना मुश्किल होगा। आज गंवाया गया अवसर देश को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि निवेशकों के मन में भारत की बेहतरी और 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाएं कम होंगी।

सन 2020 घरेलू भरोसा कायम करने का वर्ष भी होगा। मैंने इससे पहले कभी करोबारी जगत को इतना निरुत्साहित नहीं देखा। इसके लिए एक हद तक वे खुद उत्तरदायी हैं तो दूसरी तरफ कुछ मामलों में न्यायिक और सरकारी हस्तक्षेप भी इसकी वजह हैं। लोगों को दोबारा जोखिम लेना होगा। किसी भी निवेश या पूंजीगत व्यय में जोखिम रहता है और वित्तीय तंत्र को जोखिम लेने का समर्थन करना चाहिए। निवेशक यह समझते हैं कि हमारे पास राजकोषीय गुंजाइश नहीं है। सरकार इस मंदी से यूं ही बच नहीं सकती। रिजर्व बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लेकर सचेत है और मौद्रिक गुंजाइश सीमित है। लब्बोलुआब यह कि बिना रुझान में सुधार के हम इस संकट से उबर नहीं सकते। रुझान में सुधार तभी आएगा जब कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों में भरोसा पैदा होगा। सन 2020 में मुझे आशा है कि गैर अमेरिकी बाजार, अमेरिका से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और डॉलर कमजोर होगा। यह उभरते बाजारों के शेयरों के लिए सकारात्मक हो सकता है क्योंकि वैश्विक वृद्धि मजबूत होगी लेकिन नकदी की स्थिति सहज बनी रहेगी। बीते दो वर्ष में व्यापक भारतीय बाजार के कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी तरह के सकारात्मक रुझान का प्रतिफल भारी लाभ के रूप में सामने आ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम संतुलन कायम रखें और भरोसा बहाल करें। वैश्विक निवेशक यकीन करना चाहते हैं हमें उन्हें इसकी वजह देनी होगी।

गंदे खेल और टालमटोल से परहेज का आखिरी मौका

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

यह एक दशक के अवसान और संभवत: नए युग के आरंभ का वक्त है। हम जिस दशक (2010-2019) को अपने पीछे छोड़ने जा रहे हैं उसमें यह दुनिया खंडित हुई है, नाकाम हुई है, हमारे नेताओं का पतन हुआ है, अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों में घिरी हैं और हमारे चारों तरफ संघर्ष एवं विवाद नजर आते हैं। इस दशक में हमें यह अहसास हुआ है कि जलवायु परिवर्तन कोई सुदूर भविष्य का मसला नहीं रह गया है। यह घटित हो रहा है और इसके प्रभाव बढ़ते ही जाएंगे। इस दशक में हरेक साल नए रिकॉर्ड बनते रहे हैं- कभी अधिकतम तापमान का तो कभी सबसे प्रतिकूल मौसम का। लेकिन मामला सिर्फ मौसम का ही नहीं है। मुद्दा यह है कि दुनिया में लोग अपने वर्तमान को किस तरह देखते हैं और अपने भविष्य के बारे में कैसी सोच रखते हैं?

हमें मालूम है कि आज युवा बेचैन हैं और शायद पिछले किसी भी दशक की तुलना में सबसे ज्यादा बेचैनी है। अपेक्षाकृत धनी दुनिया में युवा तबका अधिक चिंतित एवं बेचैन है क्योंकि उन्हें तेजी से गर्म होती दुनिया में अपना वजूद बचाए रख पाने का तरीका ही नहीं मालूम है। लेकिन मेरे ख्याल से युवाओं को सबसे ज्यादा चिंतित यह बात करती है कि वे फर्क पैदा कर पाने में खुद को अशक्त महसूस करते हैं। उनकी जिंदगी में सारभूत एवं आवश्यक हरेक चीज को समस्या के तौर पर पेश किया जा रहा है। वे इस स्थिति को कैसे बदलेंगे? युवा इस बात को लेकर चिंतित हैं और उन्हें ऐसा होना भी चाहिए।

वहीं विपन्न दुनिया में युवाओं को अवसर की चाहत है। लेकिन उन्हें अपने आसपास भविष्य की संभावनाएं क्षीण दिखाई देती हैं। वे गांव से शहर और वहां से दूसरे देश जाना चाहते हैं। वे अपने माता-पिता की दुर्दशा से इत्तफाक नहीं रखते हैं। सरकारी स्तर पर सही व्यवस्था नहीं होने से वे समुचित औपचारिक शिक्षा से भी वंचित होते हैं फिर भी वे अपने मोबाइल फोन के जरिये मौजूदा दौर से तालमेल बिठाए हुए हैं। वे दूर चमकती रोशनी से परिचित हैं और उन्हें बखूबी पता है कि दुनिया उनका इंतजार कर रही है। वे इसे चाहते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया को टुकड़े-टुकड़े होते देखते हैं। खेती-किसानी से जुड़े उनके मां-बाप दोनों मकसद नहीं पूरे कर पाते हैं। खाद्यान्न उपजाने से जुड़े मौसमी जोखिम एवं लागत दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है और हरेक मौसम में कर्ज का जाल उलझता जाता है। लेकिन युवा ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। यह पीढ़ी एक और लिहाज से अलग है। वे निरीह या दब्बू नहीं हैं। वे अधिक के लिए भूखे होने के साथ उतावले भी हैं।

ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया के करीब हरेक हिस्से में हालात बहुत जल्द काबू से बाहर जा सकते हैं। ईंधन के दाम या शिक्षण संस्थानों के शुल्क में बढ़ोतरी का मुद्दा भी सरकारों को गिरा सकता है, सेना को सड़क पर ला सकता है और आगजनी, लूट एवं गोलीबारी की नौबत आ सकती है। विस्फोटकों से भरी यह दुनिया उबाल पर है।

यह एक विभाजित विश्व भी है। देश अब एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। हर देश केवल अपने हितों के बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन दिखावा अब नहीं रहा और असाधारण अंतसर्बद्धता एवं अंतर्निभरता के इस दौर में भारी नतीजे देखे गए हैं। साफ है कि पिछले तीन दशकों (1990-2019) में अगर स्थानीय हवा को साफ किया गया है और उत्सर्जन को काबू में रखा गया है तब भी वृद्धि का खमियाजा पर्यावरण को उठाना पड़ा है जो वजूद पर खतरा बन रहे जलवायु परिवर्तन का सबब बन रहा है। हमारे उत्तराधिकारियों को यह बात याद रखनी चाहिए।

इस दशक में याद रखने लायक कुछ और सबक भी हैं। हमारी दुनिया में हम अभूतपूर्व स्तर का आंतरिक प्रवास एवं ग्रामीण असंतोष देख रहे हैं। मैं प्रवासियों के बारे में व्यापक एवं अक्सर नकारे खुलासों की वजह से ऐसा नहीं कह रही बल्कि हमें पता है कि हमारे शहर गैरकानूनी ढंग से बढ़ रहे हैं और यह वृद्धि व्यापक एवं काबू से बाहर हो चुकी है।

यहीं पर चक्र बंद हो जाता है। सच यह है कि दिल्ली आज ठीक से सांस नहीं ले सकती है। हमारी हवा जहरीली एवं अशुद्ध है। हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमें यह समझना होगा कि करीब 30 फीसदी प्रदूषण हवा में उत्सर्जन करने वाले उद्योगों के नाते है। ये उद्योग प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन का खर्च नहीं उठा सकते हैं। वे पेट कोक जैसे गंदे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं और इस पर प्रतिबंध लग जाने के बाद कोयले या किसी भी सस्ते ईंधन का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन दिल्ली में साफ हवा की चाहत होने पर भी हम इन उद्योगों को दूसरे इलाके में नहीं भेज सकते हैं। एयरशेड तो एक ही है। मेरा मानना है कि वायु प्रदूषण सबकुछ बराबर कर देता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह औद्योगिक वृद्धि पर्यावरण की लागत में किसी रियायत के बगैर आती है। हमें शहरी एवं ग्रामीण और अमीर एवं गरीब का समावेश करने वाले विकास की जरूरत है।

धनी देशों के अमीरों के लिए भी यही सबक होना चाहिए। उनकी सरकारों ने जलवायु वार्ताओं में समता एवं न्याय की बुनियादी धारणा को ही खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन सच यह है कि यह एक साझा एयरशेड भी है। अगर अतीत में धनी देशों ने उत्सर्जन किया था तो गरीब भविष्य में ऐसा करेंगे। हमारा एक साझा भविष्य है और जलवायु प्रभावों के संदर्भ में यह उतना अच्छा नहीं लगता है।

लिहाजा अगले दशक में हम वास्तविकता के करीब रहें। अगर अपने लिए न सही तो इस ध्रुवीकृत, बेहद असमान और जोखिमों से भरपूर इस दुनिया की विरासत पाने वाले युवाओं के लिए ऐसा करें। अब खेल न खेलें और टालमटोल न करें। अगला दशक बातों पर खरा उतरने का आखिरी मौका है। हम इस मौके को नहीं गंवा सकते हैं।

कानाफूसी

मालदार माली

एक पुरानी कहावत है कि एक आदमी ने धनवान बनने के लिए प्रार्थना की और वह एक ही पेड़ से अनेक पेड़ उगाकर अमीर बन गया। बाद में उस व्यक्ति ने पेड़ का नाम ही मनी प्लांट रख दिया। बहरहाल यह तो नहीं पता कि यह कहावत सच है अथवा नहीं, लेकिन ओडिशा सरकार के अधिकारियों ने एक माली तथा साथ में सरकारी बागवानी कर्मचारी के पास से एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का पता लगाया है। अधिकारियों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर उद्धव बेहड़ा के घर तथा मयूरभंज और बालासोर जिले में रहने वाले उनके रिश्तेदारों के निवास पर छापे मारे। नकदी के अलावा बेहड़ा के पास से एक तीन मंजिला घर, 12 खाली प्लॉट, पोल्ट्री फार्म, तीन दोपहिया वाहन, बैंकों में बड़ी मात्रा में निवेश तथा जमा योजनाओं के साथ-साथ भारी मात्रा में सोने के गहने मिले।

फुले चलीं अकेले

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की दलित नेता सावित्री फुले ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थीं। कांग्रेस पार्टी ने फुले को बहराइच लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था लेकिन वह भाजपा के उम्मीदवार से हार गईं। इस हार के बाद फुले राजनीतिक गलियारों में अलग-थलग पड़ गईं क्योंकि कांग्रेस अपनी राज्य इकाई के पुनर्गठन पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब फुले अगले महीने लखनऊ में एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी जहां वह अपने अगले कदम के बारे में घोषणा कर सकती हैं।

आपका पक्ष

साइबर ठगी रोकने के हों उपाय

भारत डिजिटल लेनदेन की ओर कदम तो बढ़ा चुका है। लेकिन कुछ साइबर ठग इसकी राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन साइबर ठगी की खबरें आती हैं। हालांकि साइबर ठगी रोकने के लिए सरकार और बैंकों ने उचित कदम भी उठाए हैं। फिर भी साइबर ठगी के मामले क्यों कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी की सुरक्षा में अभी कुछ कमी या फिर लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है। कुछ कंपनियां लोगों को ऑनलाइन पुराने सामान बेचने और खरीदने का प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा रही हैं। लेकिन साइबर ठग यहां भी लोगों को ठग रहे हैं। यहां साइबर ठग लोगों से सामान के एवज में अग्रिम भुगतान की मांग कर लोगों से उनके बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की जानकारी ले रहे हैं और जानकारी मिलने के बाद खाते से पैसा निकाल रहे हैं। लोगों

को चाहिए कि वह इसके लिए भी जागरूक हों तथा ऐसी वेबसाइट पर किसी प्रकार का लेनदेन न करें। साइबर ठग, ठगी या धोखाधड़ी करने के लिए लोगों को ऑफर या पैसे दोगुना करने का झांसा देकर भी फोन करके बैंक खाते की जानकारी जुटाते हैं। कुछ ठग लोगों को फोन करके उनके बैंक खाते या एटीएम कार्ड

सरकार को साइबर क्राइम रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए

के बंद होने की बातों में उलझाकर जानकारी जुटाते हैं। जिसके बाद लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि वह किसी के झांसे में नहीं आएं। साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और दूसरों को भी करना पड़ेगा। लोगों को अपने क्रेडिट, डेबिट कार्ड के सीवीवी और ओटीपी नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए। देश में बढ़ते साइबर ठगी मामले के लिए साइबर सेल को चुस्ती दिखानी चाहिए। अगर साइबर सेल में किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत आती है तो उस पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सहूलियत भरा हो जीएसटी कानून

आयकर और जीएसटी में ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे देश में उद्योग लगाने वाले हतोत्साहित नहीं हों। देश में अभी जीएसटी एक नई प्रक्रिया है तथा इसे पूरी तरह सफल होने में कई वर्ष लग सकते हैं। सरकार को जगह-जगह शिविर लगाकर जीएसटी के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए जिससे छोटे-बड़े उद्यमियों तथा जीएसटी अदा करने वाले लोगों को इसका फायदा दिख सके। आयकर की दरों में भी कमी लाने की जरूरत है जिससे लोग आयकर रिटर्न समय पर दाखिल कर सकें। कॉरपोरेट दर में कमी किए जाने से देश के कई उद्योग खुश हैं तथा पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोगों पर आयकर की मार पड़ती है जिसमें कर की दर में सुधार की दरकार है। हर वर्ग के लिए कर की दर एक समान करने की जरूरत है जिससे देश का विकास हो सके। जीएसटी और आयकर की दर ऐसी हो जिससे सभी को आयकर देने में सहूलियत हो और व्यवसायी वर्ग जीएसटी आसानी से भर सके। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ सके। सरकार के राजस्व बढ़ने से वह राशि देश में विकास कार्यों में खर्च हो सके।

राकेश जैन, सतना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

नए साल से इस्पात उद्योग को काफी आस

विश्लेषकों का मानना है कि बुरा वक्त बीत चुका है क्योंकि जिंस कीमतों में तेजी आनी शुरू हो गई है

अदिति दिवेकर
मुंबई, 30 दिसंबर

इस्पात की मांग में कमी

- **मॉनसून के लंबा खिंचने, अमेरिका-चीन व्यापारिक टकराव और घरेलू बाजार में नकदी संकट की वजह से इस्पात खपत घटकर अप्रत्याशित स्तरों पर गिर गई**
- **उद्योग ने वित्त वर्ष 2021 के शुरू में बाजार खपत 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था**
- **पिछले दो वर्षों में घरेलू इस्पात मांग 7-8 प्रतिशत के बीच रही है**

वर्ष 2019 घरेलू इस्पात उद्योग के लिए चुनौतियों से भरा रहा। इस साल इस्पात कंपनियों के शेयरों के साथ साथ इस धातु की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

मॉनसून के लंबा खिंचने, अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव और घरेलू बाजार में नकदी संकट की वजह से इस्पात खपत घटकर अप्रत्याशित स्तरों पर आ गई थी। इस्पात की कीमतें लगभग 34 प्रतिशत गिर गईं। एडलवाइस सिक्योरिटीज में विश्लेषक अमित दीक्षित ने कहा, 'इस्पात उद्योग ने पिछले 2-3 वर्षों में इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की थी। वर्ष के दौरान हॉट-रोल्ड-कॉइल कीमतें लगातार 21 सप्ताहों तक कमजोर रहीं और इससे बाजार में खपत घट कर 4.5 प्रतिशत रह गई।'

उद्योग ने वित्त वर्ष 2021 के शुरू में बाजार खपत 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। पिछले दो वर्षों में घरेलू इस्पात मांग 7-8 प्रतिशत के बीच रही है। वर्ष 2019 में अब तक हॉट-रोल्ड-कॉइल श्रेणी के इस्पात की कीमतें 44,000 रुपये प्रति टन के ऊंचे स्तर से घटकर 33,000 रुपये प्रति टन पर आ गई हैं।

इस बीच, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील जैसी बड़ी घरेलू इस्पात कंपनियों ने स्वयं को बाजार खपत की जरूरत के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्पादन में कटौती का सहारा लिया और पूंजीगत खर्च में कमी की। सरकार के स्वामित्व वाली सेल, दिल्ली की इस्पात कंपनी जिंदल स्टील ऐंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम घरेलू बाजार में अन्य बड़ी कंपनियों में शुमार हैं।

मार्च में समाप्त तिमाही से कैलेंडर वर्ष के संदर्भ में कई प्रमुख उत्पादकों ने अपनी राजस्व वृद्धि पर दबाव महसूस किया जिससे तिमाही आधार पर मार्जिन में गिरावट को बढ़ावा मिला। इससे कमजोर व्यावसायिक परिदृश्य का संकेत मिलता है। जिंदल स्टील लॉन्ग स्टील श्रेणी के उत्पादों में ज्यादा निवेश की वजह से मार्जिन वृद्धि दर्ज करने वाली एकमात्र कंपनी रही। इस श्रेणी के राजस्व में गिरावट, फ्लैट इस्पात श्रेणी से जुड़ी कंपनियों की तुलना में बहुत अधिक नहीं रही।

फ्लैट इस्पात उत्पादों का इस्तेमाल वाहन क्षेत्र में किया जाता है जबकि लॉन्ग श्रेणी के इस्पात उत्पाद इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं। नकदी संकट की वजह से वाहन बाजार में आई कमजोरी से टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील (फ्लैट इस्पात उत्पादों के निर्माण से जुड़ी) जैसी कंपनियां ज्यादा प्रभावित हुईं।

वाहन उद्योग संगठन सायम के अनुसार अगस्त में लगातार 10वें महीने यात्री वाहन बिक्री 31.57 प्रतिशत तक घटकर 196,524 यूनिट रह गई। यह सायम द्वारा 1997-98 में आंकड़े की पेशकश शुरू किए जाने के बाद से सबसे बड़ी गिरावट थी।

अनिश्चित व्यावसायिक परिदृश्य के बीच, दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक आर्सेलरमित्तल ने भारत पर ध्यान केंद्रित किया, और निप्पॉन स्टील के साथ इसका संयुक्त उपक्रम कंपनी के लिए सकारात्मक घटनाक्रम था। इस संयुक्त उपक्रम ने इस महीने के शुरू में एस्सार स्टील का अधिग्रहण पूरा किया है।

स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसयूएफआई) के अध्यक्ष निकुंज तुरखिया ने कहा, 'भारतीय बाजार में आर्सेलरमित्तल के प्रवेश करने से 2020 में घरेलू उद्योग में बेहतर क्षमता इस्तेमाल की उम्मीद पैदा हुई है। साथ ही इससे नए वर्ष में पूंजीगत खर्च की संभावना भी बढ़ी है।'

जॉइंट प्लांट कमेटी के आंकड़े के अनुसार, भारत ने अप्रैल-सितंबर के दौरान 39.4 लाख टन का निर्यात किया, जबकि समान अवधि में 40.2 लाख टन का आयात किया गया। इस साल अप्रैल-सितंबर में खपत पिछले साल की समान अवधि के 4.845 करोड़ टन से बढ़कर 5.084 करोड़ टन पर रही।

मुंबई स्थित एक विश्लेषक ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा, 'पिछले कुछ महीनों में आयात नहीं हुआ है। यह उपभोक्ता के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारतीय कंपनियां कुछ उत्पादों के मामले में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं और ऐसे उत्पादों का आयात व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री के लिए जरूरी है।'

बुरा दौर बीत जाने की उम्मीद के साथ इस्पात उद्योग के अधिकारी 2020 में बेहतर कीमत परिदृश्य की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण खंड में खपत में तेजी आने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों में, घरेलू उत्पादकों ने कीमतों में 2,000-2,500 रुपये प्रति टन तक का इजाफा किया।

एक व्यापारी ने कहा, 'ताजा कीमत वृद्धि से मांग में कुछ सुधार आया है, क्योंकि कुछ स्टॉकिंग हुई है और इसलिए अब मांग बी-टु-बी (बिजनेस-टु-बिजनेस) से संबंधित है। जब मांग बी-टु-सी (बिजनेस-टु-कंज्यूमर) पर केंद्रित होगी, हम यह कह सकेंगे कि बाजार में वास्तविक मांग में वृद्धि हो रही है।'

ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि हालांकि अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक टकराव समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह टकराव बढ़ने की आशंका नहीं है क्योंकि इस दिशा में दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। एमके रिसर्च में विश्लेषक विशाल चंडक का कहना है, 'अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में सुधार से वैश्विक उद्योग को मजबूती मिल सकती है, जिसका घरेलू बाजार पर सकारात्मक असर दिखेगा।'

घरेलू उद्योग इसे लेकर भी आश्वस्त है कि आगामी बजट भी इस्पात क्षेत्र के लिए कुछ राहत लेकर आएगा। इस्पात क्षेत्र निर्माण उद्योग में प्रमुख उद्योगों में से एक है।

जानकारों का कहना है कि बाजार में फ्लैट यानी सपाट इस्पात उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए वाहन क्षेत्र के लिए तरलता में सुधार लाने की जरूरत होगी।

एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनेगा

भाषा
नई दिल्ली, 30 दिसंबर

- **सरकार ने चालू वर्ष में प्याज का 56,000 टन का बफर स्टॉक तैयार किया था**
- **प्याज के दाम 100 रुपये से अधिक होने पर कैबिनेट की बैठक में हुई थी चर्चा**
- **नेफेड रबी मौसम में उत्पादित प्याज की खरीदारी करेगा**

केंद्र सरकार ने अगले साल प्याज का एक लाख टन का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय किया है। हाल में प्याज के दाम में उछाल तथा आगे ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सरकार ने चालू वर्ष में प्याज का 56,000 टन का बफर स्टॉक तैयार किया था लेकिन यह बढ़ती कीमत को थामने में नाकाम रहा। प्याज के दाम अभी भी ज्यादातर शहरों में 100 रुपये किलो से ऊपर चल रहे हैं। परिणामस्वरूप, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी के जरिये प्याज आयात के लिए विवश होना पड़ा है।

अधिकारी ने कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाल में मंत्री समूह की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। यह निर्णय किया गया है कि अगले साल के लिए करीब एक लाख टन का बफर स्टॉक सृजित किया जाएगा।'

सरकार की तरफ से बफर स्टॉक रखने वाली संस्था नेफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) अगले साल यह जिम्मेदारी निभाएगा। नेफेड मार्च-जुलाई के दौरान रबी मौसम में उत्पादित होने वाले प्याज की खरीदारी करेगा। इस प्याज का जीवनकाल अधिक होता है।

खरीफ मौसम में उत्पादक क्षेत्रों में देर तक मॉनसूनी बारिश और बाद में बेमौसम भारी बारिश के कारण इस साल प्याज के उत्पादन में 26 प्रतिशत गिरावट आई है। इसका असर कीमत पर पड़ा है। सरकार ने प्याज के दाम में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें निर्यात पर पाबंदी, व्यापारियों पर भंडार सीमा के अलावा बफर स्टॉक और आयात के जरिये सस्ती दर पर प्याज की बिक्री शामिल हैं। सरकार के पास जो बफर स्टॉक था वह समाप्त हो चुका है। सस्ती दर पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए अब आयातित प्याज की बिक्री की जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 30	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,789.0	5.0	1,963.0	-1.3
Copper	6,211.0	8.4	6,491.9	6.5
Nickel	14,000.0	-20.3	14,862.6	-17.4
Lead	1,910.0	-8.4	2,201.3	4.7
Tin	17,100.0	6.5	17,807.1	1.0
Zinc	2,296.0	-3.4	2,579.9	-1.2
Gold ($/ounce)	1,512.9*	2.7	1,693.1	2.8
Silver ($/ounce)	17.9*	5.1	20.1	3.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	68.0*	13.7	68.3	12.1
Natural Gas ($/mmBtu)	2.2*	-5.2	2.2	-4.6
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	190.3	11.4	306.1	4.2
Maize	188.0*	4.9	332.0	10.0
Sugar	360.8*	4.8	488.1	-1.1
Palm oil	755.0	46.6	1,205.8	42.4
Rubber	1,626.4*	12.3	1,836.8	4.6
Coffee Robusta	1,347.0*	2.0	1,864.8	-5.6
Cotton	1,530.9	16.2	1,590.2	-3.6

* As on Dec 30, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.3& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	56.9	15728
Oil and Oilseeds	265.5	73159
Spices	0.4	16
Metal(Dec 27)		
Metal- non ferrous	3817.5	43812
Metal- precious	10923.8	408
Oil and gas(Dec 27)		
Gas	3437.8	47775
Oil	11161.8	2839

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	201.1	110906
Grains	218.5	103910
Oil and Oilseeds	1057.0	566500
Others	242.8	73005
Pulses	98.9	42380
Spices	72.3	29770

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Feb 14)	3562.4	3.4
Nickel (Dec 31)	1076.6	2.7
Zinc (Dec 31)	181.0	1.9
Aluminium Mini (Dec 31)	137.6	1.2
Gold Petal (Dec 31)	3873.0	1.1
Zinc Mini (Dec 31)	179.3	1.0
Lead (Dec 31)	151.1	0.9
Crude Palm Oil (Dec 31)	808.2	0.9
Lead Mini (Dec 31)	151.5	0.6
Gold Mini (Jan 03)	38978.0	0.5
Gold Guinea (Dec 31)	31080.0	0.1
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Jan 28)	157.0	-3.5

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Moong-Mertacity (Jan 20)	7400.0	4.0
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4715.0	2.0
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7829.0	1.4
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	951.0	1.3
Guar Seed 10 (Jan 20)	4268.0	1.2
Soyabean Indore (Jan 20)	4464.0	1.1
Coriander-Kota (Jan 20)	6597.0	0.7
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1136.0	0.6
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4240.0	0.5
Chana-Bikaner (Jan 20)	4493.0	0.2
Losers (* % Change)		
Bajra (Jan 20)	2030.0	-1.0
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2195.0	-0.8

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46995.0	2.1
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19280.0	2.0
Silver Ahm (Mar 05)	46966.0	2.0
Nickel Mumbai (Dec 31)	1076.6	1.6
Gold Ahm (Feb 05)	39080.0	0.7
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1300.0	-9.1
Aluminium Mum (Dec 31)	137.1	-3.0
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3526.4	-2.7
Alumini-Mumbai (Dec 31)	137.6	-2.7
Zinc Mini Mumbai (Dec 31)	179.3	-2.3
Copper Mum (Dec 31)	441.9	-2.2
Lead Mum (Dec 31)	151.1	-2.0

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6618.0	6.6
Maize-Sangli (Jan 20)	2109.0	5.4
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3262.0	1.1
Jeera Unjha (Jan 20)	16445.0	0.5
29 mm Cotton-Rajkot (Jan 20)	18870.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6597.0	-5.8
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	802.9	-5.1
Soy Bean Indore (Jan 20)	4464.0	-2.3
Barley Jaipur (Jan 20)	2139.0	-1.1
Bajra-Jaipur (Jan 20)	2030.0	-1.0
Bajra-Delhi (Jan 20)	2030.0	-1.0

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	104 (104)
Aluminium ingots /kg	140 (139)
Brass sheet cutting /kg	328 (328)
Brass utensil scraps/kg	310 (309)
Copper heavy scrap /kg	432 (431)
Copper utensil scraps/kg	403 (405)
Copper wire bar /kg	463 (464)
Lead ingots /kg	157 (157)
Nickel Cathodes /kg	1060 (1080)
Tin slabs /kg	1270 (1280)
Zinc slabs /kg	184 (184)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10320 (10320)
DCH - 32 /Qtl	11276 (11248)
Jaydhar /Qtl	9983 (10095)
Shankar- 6 /Qtl	11051 (11023)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	898 (898)
Castor Comm /10kg	888 (888)
Ricebran oil/10kg	820 (820)
Groundnut oil /10kg	1170 (1155)
Linseed oil /10kg	1000 (975)
Karanji /10kg	800 (780)
Palm oil /10kg	848 (830)
Sunflower exp ref /10kg	920 (910)
Sunflower oil exp /10kg	890 (875)
Soyabean ref / 10kg	925 (910)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3370-3592 (3362-3592)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	61.89 (61.72)
Brent Crude (UK)	67.82 (67.51)
Brent Crude (WTI)	61.72 (61.72)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.24 (2.23)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	287.98 (286.47)
Naptha spot /Rs/MT	45170 (45170)
LSHS spot/ M.T.	36150 (36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950 (33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	38822 (38788)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38978 (38944)
Silver.999/ kg	46130 (46320)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18792.30	18827.80
Alumini-Mumbai (M)	1 K	141.90	141.30
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2055.00	2050.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	2053.85	2050.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2130.75	2162.85
Brass-Jamnagar (M)	1 K	320.90	324.90
Cardamom-Vand. (I)*	1 K	3467.00	3450.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4315.90	4354.30
Castor Seed-Kadi (N)	X	4262.50	4262.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4407.75	4435.80
Chana Delhi (N)	1 Q	4628.70	4650.00
Chana-Akola (N)	X	4500.00	4506.25
Coriander-Gondal (N)	X	6600.00	6613.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6853.75	6800.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6895.15	7002.70
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2237.75	2222.50
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2249.70	2223.95
Cotton-Kadi (N)	1 B	18749.10	18787.95
CPO-Kandla (M)	10 K	797.00	807.20
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	831.85	845.65
Gold Ahm (M)	10 G	38791.00	38806.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31158.00	31170.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3890.00	3895.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7703.15	7869.15
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4122.75	4189.60
Guarseed-Jodhpur (I)*	1 Q	4075.00	4056.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1217.90	1261.70
Isabgulseed-Unjha (I)*	1 K	95.85	96.90
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16950.00	17000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16395.85	16369.05
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1059.10	1051.60
Kapas-Rajkot (N)	X	1061.55	1060.35
Lead Mum (M)	1 K	154.50	154.15
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2048.15	2051.90
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2447.50	2461.35
Maize-Erode (N)	X	2084.00	2112.20
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2227.50	2250.00
Maize-Sangli (N)	X	2100.45	2000.90
Moong-Merta City (N)	1 Q	7150.00	7461.50
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4797.25	4849.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	1047.50	1059.30
Paddy-Basmati-Karnal (I)*	1 Q	3217.00	3220.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3250.00	3225.00
Pepper-Ernakulam (I)*	1 K	350.00	349.60
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35216.65	35000.00
Rape mustards-Patan (I)*	20 K	831.00	832.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2078.45	2103.05
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	845.00	860.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	931.40	944.80
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	918.65	927.60
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	935.00	957.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13100.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)*	1 Q	13125.00	13133.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46192.00	46049.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4545.00	4568.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4400.00	4452.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4545.00	4585.40
Soy Bean-Akola (N)	X	4500.00	4534.00
Soymeal Indore (N)	1 T	37275.00	37588.00
Soyoil-Indore (I)*	10 K	914.50	918.60
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3305.00	3305.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3396.00	3428.55
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3270.00	3264.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3519.05	3504.75
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3350.00	3326.25
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3102.50	3102.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6000.00	6210.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2327.50	2333.75
Wheat Kota (N)	1 Q	2175.00	2185.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2250.00	2275.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2130.00	2160.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2250.00	2275.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	6101.00	6100.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	183.15	183.50

* as on Dec 27, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (सोमवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19250, 19290, 19250, 19280	145	19	1182
Jan 31	19510, 19570, 19480, 19540	4060	566	11969
Feb 28	19760, 19820, 19730, 19810	591	104	1548
Mar 31	19990, 20030, 19920, 19970	72	6	81
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2216, 2233, 2189, 2195	46550	3016	54240
Feb 20	2226, 2255, 2213, 2219	25500	1808	45700
Mar 20	2274, 2274, 2238, 2244	2320	223	5960
Apr 20	2297, 2297, 2265, 2271	700	60	680
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1133, 1140, 1133, 1135	164	35	932
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1135, 1142, 1135, 1136	1514	721	4326
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2055, 2055, 2030, 2030	20	2	90
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4224, 4296, 4224, 4268	31530	3755	62055
Feb 20	4270, 4340, 4270, 4312	19230	2372	39550
Mar 20	4306, 4376, 4306, 4352	185	33	265
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4244, 4250, 4232, 4240	4090	429	24885
Feb 20	4262, 4280, 4254, 4268	3455	394	10855
Mar 20	4240, 4280, 4240, 4262	205	32	6430
Apr 20	4288, 4288, 4238, 4264	220	33	1450
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	804, 809.1, 800.6, 808.2	4510	307	14780
Jan 31	806, 815, 801.7, 812.9	22140	1546	43760
Feb 28	795.1, 814.3, 795.1, 813	3930	290	13660
Mar 31	796.5, 803.5, 796.5, 799.3	30	3	710
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1300, 1300, 1300, 1300	1.08	3	15.48
Jan 31	1309, 1316, 1302, 1309.2	133.56	289	231.12
Feb 28	1323, 1325.2, 1322, 1323	2.88	7	1.8
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4538, 4730, 4538, 4715	21090	1526	17900
Feb 20	4619, 4732, 4619, 4721	12140	758	6820
Apr 20	4530, 4614, 4530, 4604	5200	400	11090
May 20	4550, 4607, 4550, 4582	270	23	590
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	943, 952.4, 939, 951	19275	2073	41360
Feb 20	942, 948.6, 937.6, 947.4	16280	1692	50940
Mar 20	930, 938, 930, 937	2380	129	22525
Apr 20	919, 923.8, 919, 922	115	12	1135
May 20	920, 920, 920, 920	5	1	-
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4430, 4476, 4422, 4464	50335	5098	118305
Feb 20	4460, 4494, 4442, 4478	38075	3897	164490
Mar 20	4490, 4512, 4460, 4502	16250	1772	76400
Apr 20	4524, 4536, 4500, 4530	3445	498	10755
May 20	4574, 4574, 4564, 4564	15	3	570
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7800, 7893, 7775, 7829	15700	1690	32575
Feb 20	7850, 7992, 7850, 7929	14800	1441	40055
Mar 20	8019, 8073, 8019, 8049	265	26	375
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4507, 4539, 4482, 4493	17250	1267	32210
Mar 20	4450, 4469, 4431, 4438	4630	402	9650
Apr 20	4450, 4450, 4435, 4435	40	4	410
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7392, 7400, 7392, 7400	100	4	25
Feb 20	7427, 7427, 7070, 7070	50	2	25
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3548.6, 3583.1, 3548.6, 3562.4	1.1	11	7.3
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6597, 6674, 6510, 6597	3200	296	9200
Apr 20	7127, 7269, 7110, 7196	1780	164	6750
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	16375, 16560, 16300, 16445	483	155	1941
Mar 20	15940, 16000, 15895, 15965	207	65	855
Apr 20	15590, 15715, 15590, 15620	30	8	204
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6676, 6738, 6534, 6618	2985	525	6565
Apr 20	6472, 6622, 6424, 6510	1020	197	4225
May 20	6510, 6600, 6510, 6536	20	4	30

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	135.55, 138.2, 135.3, 135.8	35	7	290
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	138.5, 138.5, 137.5, 137.9	14	12	101
Jan 31	137, 137.6, 136.9, 137.45	2541	1556	5206
Feb 28	137.35, 137.95, 137.35, 137.8	60	44	144
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	443.15, 443.15, 440.75, 442.3	87.5	32	775
Jan 31	444.25, 445.9, 444.25, 445.35	6487.5	2195	12872.5
Feb 28	448.45, 450.25, 448.45, 449.7	77.5	31	205
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	151.05, 151.05, 151.05, 151.05	10	2	205
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	149.7, 150.7, 149.7, 149.95	5	5	20
Jan 31	152.55, 152.7, 152.35, 152.65	1780	1156	4914
Feb 28	153.1, 153.2, 153, 153.1	23	23	64

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1077.3, 1077.3, 1076.6, 1077	3	2	37.5
Jan 31	1045, 1048.5, 1042.6, 1046.6	5923.5	3532	2736
Feb 28	1044, 1045.3, 1043.1, 1044	21	8	64.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	181.05, 181.05, 181, 181.05	10	2	325
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	179.3, 179.75, 179.1, 179.55	49	41	459
Jan 31	180.65, 181.3, 180.55, 181.1	12027	6982	20110
Feb 28	181.4, 181.9, 181.15, 181.55	1109	667	1799
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	39067, 39090, 38910, 38924	5.37	4489	16.17
Apr 03	39139, 39139, 39016, 39028	0.22	175	5.39
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30782, 31100, 30782, 30941	0	2	0
Jan 31	31130, 31150, 31061, 31090	0	144	0.01
Feb 28	31439, 31439, 31019, 31112	0	16	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	38993, 38994, 38701, 38765	0.37	1653	0.31
Feb 05	39097, 39150, 38890, 38901	0.55	4476	1.05
Mar 05	39119, 39120, 38915, 38931	0.02	222	0.08
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3870, 3870, 3870, 3870	0	1	0
Jan 31	3909, 3912, 3893, 3896	0	677	0.01
Feb 28	3902, 3915, 3885, 3888	0	67	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46139, 46956, 46139, 46623	295.08	8064	336.09
May 05	47335, 47415, 47070, 47123	2.16	71	7.44
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46877, 47049, 46550, 46659	29.43	20397	26.73
Apr 30	47444, 47445, 47060, 47173	1.17	951	2.96
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	47050, 47050, 46550, 46654	105.25	15734	59.49
Apr 30	47440, 47440, 47062, 47161	1.7	317	2.82

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Jan 28	158.4, 161.4, 158.4, 159.1	69964mb	31227	42825mb
Feb 25	157.1, 158.1, 156.5, 156.7	4141mb	2067	9746mb
Mar 26	157.5, 158.3, 156.7, 157	131mb	99	169mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4433, 4448, 4403, 4419	5455bl	32216	3822bl
Feb 19	4414, 4421, 4403, 4418	135bl	1096	145bl
Jun 19	4415, 4415, 4415, 4415	0bl	1	0bl

सायं सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19200, 19230, 19190, 19210	323	45	1365
Jan 31	19350, 19530, 19350, 19460	4932	657	11480
Feb 28	19650, 19750, 19650, 19700	166	32	1280
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1133, 1137.5, 1128, 1132	284	64	916
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1134.5, 1139, 1127.5, 1133	2167	1102	4363
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	785.7, 810.3, 770.7, 804	17530	1115	15970
Jan 31	793.6, 817.8, 776.9, 805.7	67180	4337	45460
Feb 28	793.6, 813.1, 778.1, 803.1	12440	915	12440
Mar 31	789, 803.3, 778, 800.2	690	55	690
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	939, 950, 924.6, 939	44125	4924	41785
Feb 20	939, 948, 925.8, 936.6	33835	3690	48810
Mar 20	927.2, 937.8, 917.6, 926.6	10710	1136	20785
Apr 20	904, 920, 902, 912.8	570	81	1080
May 20	916.4, 916.4, 916.4, 916.4	5	1	5

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	137.05, 137.55, 135.1, 137.05	170	24	340
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	136.05, 139.2, 136, 137.55	50	17	118
Jan 31	136.85, 137.35, 136.25, 137.15	5628	3161	4997
Feb 28	137.1, 137.6, 136.9, 137.45	80	76	112
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	441, 443, 440.15, 441.9	682.5	234	1540
Jan 31	444.9, 445.7, 444.1, 444.85	17752.5	6010	11025
Feb 28	449.75, 449.75, 448.55, 449.05	230	91	167.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	150.9, 151.2, 150.9, 151.1	45	9	215
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	152.5, 152.75, 152.25, 152.4	6232	3559	4508
Feb 28	153, 153.2, 152.8, 152.95	93	91	57
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1060, 1082.5, 1047.6, 1076.6	78	44	97.5
Jan 31	1034.5, 1048.4, 1027.1, 1045.9	20859	12483	1393.5
Feb 28	1027.8, 1046.6, 1024.3, 1045	190.5	125	57
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	177.95, 183.6, 177.95, 181	250	42	640
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	178.15, 181.7, 178.15, 179.25	200	197	575
Jan 31	179.85, 181.2, 179.85, 180.9	32849	18327	17001
Feb 28	181.1, 181.85, 180.95, 181.35	979	696	949
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	38930, 39095, 38787, 39080	11.85	10134	15.99
Apr 03	39067, 39182, 38887, 39173	0.63	511	5.3
Gold Guinea MCX(8 G)				
Jan 31	31030, 31146, 30981, 31118	0	434	0.01
Feb 28	31149, 31390, 30984, 31074	0	38	0
Mar 31	30998, 31000, 30998, 30999	0	3	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	38805, 38995, 38685, 38978	1.15	9707	0.5
Feb 05	38919, 39060, 38760, 39041	1.05	8456	0.94
Mar 05	38971, 39098, 38795, 39071	0.06	441	0.07
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Jan 31	3892, 3910, 3885, 3903	0.01	1685	0.01
Feb 28	3889, 3895, 3877, 3892	0	152	0
Mar 31	3885, 3978, 3861, 3920	0	21	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46861, 47073, 46480, 46966	741.75	20417	299.13
May 05	47373, 47533, 46986, 47416	4.14	136	6.18
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46900, 47092, 46512, 46995	84.46	56779	24.35
Apr 30	47349, 47540, 47000, 47449	4.1	2923	2.87
Jun 30	48000, 48135, 48000, 48068	0	2	0.02
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46900, 47100, 46517, 46992	268.25	40371	49.63
Apr 30	47363, 47550, 47004, 47439	4.25	768	2.75

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Jan 28	162.5, 162.7, 156.2, 157	204031mb	96005	37803mb
Feb 25	159, 159.2, 153, 154.7	12209mb	7133	9843mb
Mar 26	158, 158.7, 154, 154.9	290mb	215	130mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4394, 4430, 4379, 4416	24743bl	147480	2718bl
Feb 19	4406, 4427, 4379, 4413	567bl	4740	121bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

दशक में बैंकों पर बढ़ी सरकार की निर्भरता

बैंक विलय, नोटबंदी, बड़े घोटालों का पर्दाफाश, आईबीसी, नए बैंक लाइसेंसों का आवंटन दशक के अहम घटनाक्रम रहे

अनूप रॉय

पिछले दशक में सरकार के आर्थिक एजेंडा का आधार बैंकिंग क्षेत्र था। यह ऐसा दशक रहा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज के माहौल में बड़े बदलाव किए जाने के बावजूद वे चुनौतियों से पार पाने में सफल रहे। निस्संदेह यह दशक बैंकिंग क्षेत्र में अहम घटनाक्रम से भरपूर रहा। ये घटनाक्रम 1970 के दशक में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी बड़े रहे हैं। इन घटनाक्रमों में 23 नए बैंक लाइसेंस, बैंक विलय, मुद्रा संकट की वजह से डॉलर जमाओं में बढ़ोतरी, नोटबंदी, बड़े घोटालों का पर्दाफाश, डिजिटलीकरण, बैंक बोर्ड प्रशासनिक सुधार, निजी बैंकों के जाने-माने प्रमुखों का हटना, रिकॉर्ड फंसे कर्ज, ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) बनना आदि शामिल हैं।

इस दशक में सरकार को बैंकों में नई पूंजी डालने की जरूरत महसूस हुई। इस दशक की शुरुआत में सरकार वैश्विक ऋण संकट से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को उबारने के लिए प्रोत्साहन पैकेज देने में व्यस्त थी। खुद बैंक भी जूझ रहे थे कि कृषि ऋण माफी योजना कैसे लागू की जाए। बैंकों को सबवेंशन स्कीम और घाटे के रूप में प्रोत्साहन पैकेजों की कीमत चुकानी पड़ी। यह रुझान अब भी जारी है। बड़ी कंपनियों में फंसे कर्जों और बड़े घोटालों ने देश के बैंकिंग उद्योग को हिला दिया है।

अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के प्रबंध साझेदार अश्विन पारेख ने कहा, 'अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बैंकिंग तंत्र पर निर्भरता जरूरत से अधिक है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद प्रोत्साहन पैकेज शुरू किए गए, जिसकी कीमत बैंकिंग तंत्र को चुकानी पड़ी।' लेकिन ऐसी निर्भरता की सरकार को भी कीमत चुकानी पड़ती है। न केवल बैंकों में नई पूंजी डालने की जरूरत है बल्कि बोर्डों में भी बदलाव की दरकार है। पारेख के मुताबिक सरकार को सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51 फीसदी से कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों के विलय से सार्थक नतीजे निकलने की संभावना नहीं है।

जब बड़े कर्जदारों ने डिफॉल्ट करना शुरू किया तो बैंक अधिकारियों को गलत व्यावसायिक फैसलों के लिए घेरा गया। इससे बैंकरों ने ऋण देने में हाथ खींच लिए। इससे अर्थव्यवस्था में ऋण वितरण कमजोर पड़ा। यह भी भारी मंदी की एक वजह रहा है।

दशक का एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी था कि देश के निजी बैंकों की कमान संभाल रहे लोगों को बैंक छोड़ने पड़े। बैंक हमेशा ही सरकार के लिए महत्त्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने सरकारी बैंकों के जरिये अपने आर्थिक और सामाजिक एजेंडे को आगे बढ़ाया। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद बैंकिंग क्षेत्र मुश्किल दौर से गुजरा क्योंकि सरकार ने रातों-रात 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाते हुए 86 फीसदी नकदी चलन से बाहर कर दी। लेकिन लगभग पूरा पैसा आर्थिक तंत्र में आ गया, जिससे नोटबंदी को लेकर सवाल उठते हैं। हालांकि इससे डिजिटलीकरण में तेजी आई। मोबाइल आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), इमिडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) और अब 24 घंटे नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) से भारत में बैंकिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। ऐसे डिजिटल ढांचे की नींव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में रखी गई। लेकिन राजग सरकार ने इस पहल को नई ऊंचाई पर पहुंचाया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी *(फाइल फोटो)*

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने अप्रैल 2014 से 23 बैंक लाइसेंस जारी किए थे। दो को अप्रैल 2014 में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस दिए गए। वहीं 11 को अगस्त 2015 में भुगतान बैंक लाइसेंस दिए गए। इसके अलावा 10 को सितंबर 2015 में लघु वित्त बैंक के लाइसेंस दिए गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश भर में लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक बनाने की मुहिम की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 12.5 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन खातों में से आधे से अधिक निष्क्रिय हैं। इसके बाद बैंकरों के साथ दो दिवसीय विचार मंथन सत्र 'ज्ञान सत्र' का आयोजन किया गया और फिर 'इंद्रधनुष' परियोजना पर काम शुरू हुआ। इस परियोजना के तहत केंद्र ने बैंक बोर्ड में बदलाव की कवायद शुरू की। इसके लिए एक बैंक बोर्ड ब्यूरो तैयार करना अहम था। इसके अलावा फंसे हुए कर्ज की पहचान करने और बैंकों के पर्याप्त पुनर्पूंजीकरण के जरिये समाधान की कोशिश की गई। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने सरकारी बैंकों की कमान संभालने के लिए निजी क्षेत्र से नियुक्ति का फैसला किया।

दशक में बदला परिदृश्य

दिसंबर 2015 में रघुराम राजन ने बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता का आकलन कराने का फैसला किया। तीन सालों की इस प्रक्रिया के बाद बैंकिंग क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा फंसे कर्ज का पता चला और इनमें से ज्यादातर के पास पर्याप्त पूंजी प्रावधान कवर की कमी थी। साफतौर पर सरकारी बैंकों के पास इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। नियमित तौर पर बैंकों को पूंजीगत मदद देने के साथ ही अक्टूबर 2017 में 2.11 लाख करोड़ रुपये की नई पूंजी देने का वादा किया गया। बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे अहम, आईबीसी कानून इस दशक में ही अगस्त 2016 में बना। अब नए कानून की ताकत पाकर बैंकर भी आक्रामक दिखे और उन्होंने बड़े उद्योगपतियों से बैंक का कर्ज लौटाने को कहना शुरू किया। पारेख ने बताया, 'एस्सार स्टील पर फैसला होने के बाद आईबीसी और एनसीएलटी ने सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि ऋणदाताओं की समिति को सशक्त बनाने की जरूरत है।' इस कानून की मदद से बैंकों ने अपने फंसे हुए कर्ज में से 4-5 लाख करोड़ रुपये वसूलने में सफलता पाई जिससे बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा सुधार दिखा। जून 2019 में 44 सूचीबद्ध बैंकों के कुल फंसे कर्ज 9.27 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गए जो मार्च 2018 में 10 लाख करोड़ रुपये थे। इसमें आगे भी कमी आनी चाहिए थी लेकिन आर्थिक वृद्धि में गिरावट की वजह से फंसे कर्ज एक बार फिर से जमा होना शुरू हो गए। सितंबर के अंत तक आईबीसी में 10,860 मामले लंबित थे हालांकि इन मामलों में महज 15 फीसदी का ही समाधान हो सका।

इस दशक में सरकार ने बैंकों के विलय पर जोर दिया। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने पांच सहयोगी बैंकों के अलावा भारतीय महिला बैंक का विलय किया। आईडीबीआई का निजीकरण कर उसे एलआईसी को बेच दिया गया। इस साल अप्रैल में देना और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। अगस्त में सरकार ने कहा कि पीएनबी और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किया जाएगा। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय के अलावा, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा। 2018 में देश के बैंकिंग उद्योग में तब हलचल मच गई जब दो जानेमाने आभूषण कारोबारियों ने फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिये पीएनबी बैंक में करीब13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में 71,500 करोड़ रुपये के घोटाले सामने लाए जिनमें से ज्यादातर सरकारी बैंकों में हुए थे। 2019 में एक बड़े सहकारी बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक ने एक रियल एस्टेट समूह को अपना 70 फीसदी से अधिक ऋण दे दिया जो बाद में दिवालिया हो गई।

बैंकिंग क्षेत्र की सुर्खियां

2013:

सितंबर: रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर बने, रुपये में गिरावट को रोकने के लिए एनआरआई की जमाओं का इस्तेमाल किया

2014:

मई: बैंक बोर्ड में सुधार के लिए पी जे नायक समिति बनी

अगस्त: जन धन योजना

अप्रैल-सितंबर: 23 नए बैंक लाइसेंस दिए गए जिनमें बंधन और आईडीएफसी बैंक भी शामिल हैं

2015:

जनवरी: ज्ञान संगम, प्रोजेक्ट इंद्रधनुष, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन

अगस्त: बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा

2016:

अगस्त: ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया कानून लागू

नवंबर: नोटबंदी, 500 और 1000 रुपये के नोट पर लगी पाबंदी, डिजिटलीकरण पर बढ़ा जोर

2017:

अप्रैल: एसबीआई ने अपने पांच सहयोगी बैंकों और एक अन्य बैंक का विलय किया और यह शीर्ष 50 बैंकों की सूची में शामिल हो गया

मई: आरबीआई कानून में संशोधन की वजह से शीर्ष बैंक की भूमिका समाधान और वाणिज्यिक फैसले गलत होने पर बैंकरों को दोषमुक्त करने के लिहाज से अहम हो गई

अक्टूबर: सरकार ने सरकारी बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की

2018:

जनवरी: नीरव मोदी ने पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया

फरवरी: आरबीआई के परिपत्र में एक दिन के डिफॉल्ट का नियम जारी किया गया

2019:

जनवरी: एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदी

अप्रैल: देना और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ

जून: आरबीआई ने एक दिन के डिफॉल्ट नियम को खत्म किया और बैंकों को इस प्रस्ताव पर फैसला लेने का विकल्प दिया

अगस्त: सरकार ने विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की

नवंबर: उच्चतम न्यायालय ने आईबीसी में ऋणदाताओं की समिति को प्राथमिकता देते हुए ताकत दी, एस्सार स्टील की बिक्री की गई।

पृष्ठ 1 का शेष

अरबपतियों की सूची में नए चेहरे

अरबपतियों की सूची से बाहर अनिल अंबानी

रिलेक्सो फुटवियर्स के प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक रमेश दुआ अरबपति समूह के नवीनतम सदस्य हैं और उन्होंने सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है। उनके परिवार की परिसंपत्ति पिछले 12 महीनों के दौरान 65 प्रतिशत बढ़कर 10,800 करोड़ रुपये हो गई है। दिसंबर 2018 के अंत में उनके परिवार की शुद्ध परिसंपत्ति 6,500 करोड़ रुपये (90 करोड़ डॉलर) थी।

इस वर्ष सितंबर के अंत में दुआ परिवार की रिलेक्सो में 71 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। चालू कैलेंडर वर्ष में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 72 प्रतिशत बढ़ा है और इस तरह यह बाजार में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला उपभोक्ता शेयर रहा है।

इस सूची में कृषि रसायन निर्माता कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज के मयंक सिंघल का नाम भी जुड़ा है। इस साल पीआई इंडस्ट्रीज का शेयर भाव 70.4 प्रतिशत तक उछला है। सिंघल परिवार की शुद्ध परिसंपत्ति अब करीब 10,400 करोड़ रुपये (1.5 अरब डॉलर) हो गई है, जो दिसंबर 2018 के अंत में 6,000 करोड़ रुपये थी। कंपनी में सिंघल परिवार की 51.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

बेंगलूरु स्थित रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक इरफान रज्जाक भी अरबपति समूह में शुमार हो गए हैं। कंपनी में अब उनके परिवार की हिस्सेदारी का मूल्य करीब 8,800 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें इस वर्ष अब तक 53.4 प्रतिशत तेजी आई है।

कंपनी में रज्जाक परिवार की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। समूह में शामिल नए चेहरों में जीएमआर इन्फ्रा के जीएम राव, एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक के संजय अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेस के मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल शामिल हैं।

दूसरी ओर सोलर इंडस्ट्रीज के सत्यनारायण नवल, हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स के आर जी चंद्रमोगन, अंजता फार्मा के मन्नालाल अग्रवाल और नुस्ली वाडिया अरबपतियों की सूची से बाहर हो गए हैं।

प्रमुख कंपनियों में उनके शेयरों के मूल्य में गिरावट के कारण ऐसा हुआ है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में नुस्ली वाडिया की हिस्सेदारी बॉम्बे बर्मा के पास है। यह मुनाफे और बाजार पूंजीकरण के लिहाज से एक छोटी कंपनी है। एसआरएफ के अरुण भरत राम और टीवीएस मोटर के वेणु श्रीनिवासन के मामले में भी ऐसा ही है।

इंटरनेट राजनीति का डिजिटल अर्थव्यवस्था पर असर

पीरजादा अबरार और रोमिता मजूमदार

देश में समय-समय पर इंटरनेट पर रोक के कारण एमेजॉन और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के भारत के कुल कारोबार में कम से कम 18 से 20 फीसदी गिरावट आई है। उद्योग के सूत्रों ने यह जानकारी दी। आम तौर पर ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दिसंबर व्यस्तता का महीना होता है। इस समय उनके पास बड़ी तादाद में ऑर्डर आते हैं और एक दिन इंटरनेट बंद होने का बिक्री पर भारी असर पड़ता है।

ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार में 20 फीसदी की गिरावट देखी गई

नए नागरिकता कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के कारण देश के कई हिस्सों में मोबाइल डेटा सेवाएं स्थगित कर दी गईं और प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसका ई-कॉमर्स कंपनियों के कारोबार पर ऐसे समय असर पड़ा है, जब ज्यादातर ई-कॉमर्स कंपनियों की देश भर में साल के अंत की त्योहारी सेल चल रही है। ई-कॉमर्स कंपनियों ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के उत्तर-पूर्वी हिस्सों और दिल्ली में बिक्री में गिरावट दर्ज की है, जहां हाल में अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। उद्योग के एक स्रोत ने नाम न प्रकाशित करने का आग्रह करते हुए कहा, 'यह असर बड़ा है क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनियों (एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी) ने कारोबार में कम से कम 20 फीसदी गिरावट दर्ज की है। यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब इन कंपनियों की त्योहारी सेल चल रही है और वे मझोले और छोटे शहरों और कस्बों में तगड़ी बिक्री की उम्मीद कर रही हैं।'

उन्होंने कहा, 'डिजिटल भुगतान कंपनियों और बैंकों पर भी बड़ा असर पड़ा है क्योंकि उनमें भी हरेक काम के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अहम है।' उद्योग के एक अन्य सूत्र ने कहा कि एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सी ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकार को बताया है कि बार-बार इंटरनेट पर रोक के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। उद्योग के एक सूत्र ने नाम न प्रकाशित करने का आग्रह करते हुए कहा, 'हमें नहीं पता कि ये विरोध-प्रदर्शन कब बंद होंगे। वहीं कुछ अन्य मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर रोक लगाना सबसे बेहतर समाधान नहीं है। अधिकारी इसका इस्तेमाल धारा 144 की तरह बार-बार कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'उन्हें सुरक्षा के लिए अन्य तरीके खोजने चाहिए, यह लंबे समय इस्तेमाल किया जा सकने वाला मॉडल नहीं है।' हालांकि इन समस्याओं को अधिकारी देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वीकृत कोलेटरल डेमेज मानते हैं। दूरसंचार कंपनियां अपने लाइसेंस के नियमों के तहत इंटरनेट सेवाएं रोकने के सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। पिछले साल इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिलेशंस की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत में वर्ष 2012 से 2017 के बीच विभिन्न मौकों पर इंटरनेट पर रोक लगने के कारण औसतन हर घंटे 1,86,332 डॉलर का नुकसान हुआ। इसी रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि भारत में 16,315 घंटे इंटरनेट पर रोक के कारण अर्थव्यवस्था को आलोच्य अवधि में 3.04 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

ईवाई इंडिया में पार्टनर और नैशनल लीडर (ई-कॉमर्स और कंज्यूमर इंटरनेट) अंकुर पाहवा ने कहा, 'इस डिजिटल और कनेक्टेड दुनिया में इंटरनेट लगभग एक जरूरी वस्तु बन चुका है। सेवा में अवरोध से न केवल उपभोक्ता इंटरनेट कंपनियों पर फिनटेक कंपनियों के कारोबार पर भी असर पड़ता है। इसका असर ऑफलाइन विक्रेताओं पर भी पड़ता है।'

फॉरेस्टर रिसर्च में वरिष्ठ पूर्वानुमान विश्लेषक सतीश मीना ने कहा कि इंटरनेट ने ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान कंपनियों को प्रभावित किया है। मीना ने कहा, 'इसका डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, जो यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है। इसकी वजह यह है कि ऐसा बार-बार होता है तो यूजर इन कंपनियों (फ्लिपकार्ट और एमेजॉन) पर निर्भर रहने के बजाय अन्य विकल्प तलाशेंगे।'

देश में फ्लिपकार्ट, एमेजॉन और पेटीएम जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कारोबार में चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत के ऑनलाइन खुदरा बाजार में दबदबे के लिए वॉलमार्ट अमेरिकी दिग्गज एमेजॉन को फ्लिपकार्ट के जरिये चुनौती दे रही है। वॉलमार्ट ने पिछले साल मई में 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया था। जेफ बेजोस की अगुआई वाली एमेजॉन ने 2016 में भारत में पांच अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था।

सालाना आंकड़े

2012	3
2013	5
2014	6
2015	14
2016	31
2017	79
2018	134
2019*	101

* so far

देश में सबसे लंबे समय तक इंटरनेट पर रोक

150 दिन और अब भी जारी कश्मीर(4 अगस्त 2019 से)

133 दिन कश्मीर (8 जुलाई से 19 नवंबर 2016 तक)

100 दिन दार्जिलिंग (18 जून से 25 सितंबर 2017 तक)

373

वर्ष 2012 से 2019 के बीच इंटरनेट बंद होने की कुल संख्या

स्रोत: सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर रिपोर्ट

राज्य के आंकड़े

जम्मू कश्मीर	180
राजस्थान	67
उत्तर प्रदेश	25
हरियाणा	13
गुजरात	11
बिहार	11
महाराष्ट्र	10
पश्चिम बंगाल	9
मेघालय	5
त्रिपुरा	5
मणिपुर	5
ओडिशा	5
मध्य प्रदेश	5
अरुणाचल प्रदेश	4
असम	3
नगालैंड	3
उत्तराखंड	2

वैल्यू चेन खुदरा कारोबारियों को लगा मामूली झटका

समरीन अहमद

वाहन और रोजमर्रा के सामान वाले क्षेत्र (एफएमसीजी) में इस साल संकट की स्थिति बनी रही लेकिन देश भर में छाई मंदी का फैशन-खुदरा वैल्यू चेन क्षेत्र पर ज्यादा असर नहीं दिखा। कंपनियों को बिस्कुट से लेकर कार बेचने में काफी संघर्ष करना पड़ा लेकिन किफायती फैशन सामग्री की मांग बरकरार रही।

ज्यादातर वैल्यू चेन खुदरा कंपनियां मसलन वी मार्ट, 1-इंडिया फैमिली मार्ट और वी-बाजार में दूसरी तिमाही में मंदी की स्थिति बनती दिखी लेकिन तीसरी तिमाही में त्योहार के दौरान बिक्री बढ़ने और शादी के सीजन की वजह से काफी सुधार दिखा। इन कंपनियों द्वारा बेचा जाने वाले 90 फीसदी सामान 1,000 रुपये से कम है। इस क्षेत्र में वी-मार्ट एक बड़ी कंपनी है जिसकी कमाई का दायरा 1,400 करोड़ रुपये से ज्यादा है और दूसरी तिमाही में इसकी वृद्धि महज 1 फीसदी रही हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष में सालाना चक्रवृद्धि दर 20 फीसदी तक रही। वी मार्ट के सीओओ समीर मिश्रा का कहना है, 'हम यह देख रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक-डेढ़ साल पहले के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमारी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा है। समान स्टोर की वृद्धि कम है लेकिन हम दूसरे स्टोर खोल रहे हैं और विस्तार की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं।' गुड़गांव के इस खुदरा चेन के 257 स्टोर फिलहाल देश भर में चल रहे हैं और भविष्य में इसका लक्ष्य 60 नए स्टोर खोलने का है। फ्यूचर रिटेल के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश बियाणी को उम्मीद है कि उनके कुल कारोबार में इस साल दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज होगी। फ्यूचर रिटेल ही फैशन वेंचर एफबीबी संचालित करती है। अगले दो सालों में 350 करोड़ रुपये का निवेश कर फ्यूचर ग्रुप की 140 आउटलेट खोलने की योजना है।

हालांकि कुछ छोटी कंपनियां मसलन वी-बाजार के लिए राह इतनी आसान नहीं रही और इसे अपनी लागत में कटौती के उपाय करने के साथ ही नए स्टोर खोलने की योजना रद्द करनी पड़ी। वी-बाजार मुख्यतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदीभाषी क्षेत्रों में कारोबार करती है और इसने इस साल 30 नए स्टोर खोलने की योजना थी लेकिन कंपनी अब तक केवल 15 स्टोर ही खोल पाई।

1-इंडिया फैमिली मार्ट ने जुलाई, अगस्त और सितंबर जैसे महीने में 27 फीसदी की वृद्धि दर्ज की लेकिन वित्त वर्ष 2020 में 40 स्टोर खोलने के बजाय यह महज 27 स्टोर ही खोल सकेगी। 1-इंडिया फैमिली मार्ट के मुख्य कार्याधिकारी जे पी शुक्ला कहते हैं, 'सरकार बाजार में नकदी बढ़ाने की दिशा में पहल कर रही है ऐसे में हम 2020 में अच्छी शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं।' विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक खुदरा शृंखला को पूरे साल कारोबार बढ़ाने की जरूरत है और उन्हें मार्जिन बढ़ाने के लिहाज से केवल त्योहारी सीजन की बिक्री पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।

थर्ड आईसाइट के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी देवांग्शु दत्ता ने एक ब्लॉग में कहा, 'घरेलू स्तर पर बड़े आर्थिक मदद की कोई उम्मीद नहीं है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी हलचल जैसी स्थिति है ऐसे में हमें थोड़ा संभल कर कदम उठाना चाहिए।'